ble to solve the problem, I believe, provided we all cooperate wholeheartedly to bring in a new generation. My hon. friend, Shri George Fernandes, said that the only solution is socialism, to bring in a socialistic society. It may be. But I am an unsocial socialist. I do not know how far I can go with him.

श्री रवि राय : पी०ए०सी० के जवानों को आप कब हटायेंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we take up the next item regarding U. P. teachers. SHRI Prakash Vir Shastri.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगाव) : सभी तरफ के सदस्यों ने मांग की है कि स्कूलों और कालेजों के नाम के पहले जो जाति सूचक और धर्म सूचक शब्द लगे रहते हैं, इनको हटाया जाए । इसका आपने उत्तर नहीं दिया है । आप इसका भी उत्तर दें । क्या आपके अन्दर भी प्रतिक्रियावाद घुसा हुआ है ? क्यों आप ऐसा नहीं करते हैं.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is over; no further questions. Shri Prakash Vir Shastri.

16.05hrs.

DISCUSSION *RE* : DEMANDS OF SCHOOL TEACHERS IN U. P.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up the discussion regarding demands of teachers of Higher Secondary Schools in U. P.

Mr. Prakash Vir Shastri. He will take twelve minutes.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The Business Advisory Committee decided that we would sit longer.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : We decided two hours for that debate and two hours for this debate. This is what we decided. Five minutes this way or that way is a different matter. But the time is distriubted like this. I know Shastriji always adheres to the time limit.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : ऐसे अवसर इस सदन में बहुत ही कम आए हैं जबकि छात्रों के बाद उनके गुरुओं की चर्चा विवाद का विषय बने हों । लेकिन यह सौभाग्य का विषय है कि आज का दिन संसद् ने शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यों तो सारे देश में ही प्रारम्भ से शिक्षा की उपेक्षा चलती रही है । क्योंकि विश्व में जो देश शिक्षा के ऊपर व्यय करते हैं, भारत का उन में सब से नीचे के जो राष्ट्र हैं उन में दूसरा नम्बर है । दुनिया में सब से कम शिक्षा पर व्यय करता है अफगानिस्तान और उसके बाद नीचे से दूसरा नम्बर भारतवर्ष का है । भारत में भी सब से दयनीय स्थिति जिस राज्य को है वह है उत्तर प्रदेश । स्वयं पहले जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं डा० श्रीमाली उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और अध्यापकों की स्थिति बड़ी दयनीय है । आप से पहले श्री चागला जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने भी इस सत्य को स्वीकार किया था और आपने भी कुछ दिन पहले इस सत्य को स्वीकार किया है । लेकिन मेरा कहना यह है कि इस सत्य को स्वीकार करने या अध्यापकों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने मात्र से अगर उनकी समस्या का समाधान हो जाता तो शायद इस चर्चा को छेड़ने की मुझे आवश्यकता अनुभव न होती ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज तक अध्यापकों ने अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आन्दोलनों और प्रदर्शनों का सहारा नहीं लिया । सब से पहले यह दुखद प्रसंग भारतवर्ष में उस दिन आया जिस दिन देश के अध्यापकों ने एकत्र होकर एक मौन प्रदर्शन संसद् भवन के सामने किया । लेकिन जब सरकार ने उस के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया तब विवश हो

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कर अब देश के अध्यापकों को और विशेष कर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को हड़ताल, सत्याग्रह और जेल आदि, इस प्रकार के साधनों का सहारा लेना पड़ा । इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती जब किसी देश के राष्ट्रनिर्माताओं को सड़कों के ऊपर प्रदर्शन और हड़ताल करने को विवश होना पड़े और नारे लगाने पड़ें । यह एक ऐसी बात है जिस का प्रभाव छात्रों पर भी पड़ना स्वाभाविक है । आज उत्तर प्रदेश में लगभग आठ हजार अध्यापक जेलों में बन्द हैं जिन में से लगभग डेढ़ सौ महिलायें हैं ।

आखिर इन गरीब अध्यापकों की मांगें क्या हैं ? बड़ी मामूली इनकी मांगें हैं । मुख्य रूप से इनकी पांच मांगें हैं । पहली मांग तो यह है कि उनको जो मासिक वेतन मिलता है वह सीधा सरकार के खजाने से उनको मिलना चाहिये जैसे कि केरल की सरकार ने या मैसूर की सरकार ने किया हुआ है ।

दूसरी उनकी मांग यह है कि जब संविधान की 39 वीं धारा में स्वीकार किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा तो फिर आपने उत्तर प्रदेश में दो श्रेणियां क्यों रखी हुई हैं ? राजकीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते पृथक् हैं और सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते पृथक हैं । उनको एक समान करना चाहिये ।

तीसरी मांग उनकी यह है कि कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिये हैं उनको शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जाए ।

चौथी मांग उनकी यह है कि जे०टी०सी० के जो अध्यापक हैं उनके वेतन मान आप ठीक करें और स्कूलों में काम करने वाला जो नान-एजुकेशनल स्टाफ है, क्लर्क आदि दूसरे लोग हैं उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार होना चाहिये ।

पांचवी उनकी मांग यह है कि जिन अध्यापकों के पिछले वेतन रुके हुए हैं वे उनको मिलने चाहियें । इस कमर तोड़ महंगाई के समय में उनको समय पर वेतन न मिलने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और चूंकि उनके वेतन रुके पड़े हैं इस वास्ते उनके सामने बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है अब आप पहली मांग को लें ।

16.10 hrs

[SHRI GADILINGANA GOWD *in the Chair*]

उनकी पहली मांग यह है कि सरकारी खजाने से उनको वेतन दिया जाए । कुछ दिन पहले जब यह बात यहां आई थी तब यह कहा गया था कि ऐसा करने से सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ और पड़ जाएगा जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार उठाने में समर्थ नहीं है । मैं शिक्षा मंत्री की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब चौधरी चरण सिंह की संविद् की सरकार थी तब उस सरकार ने इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी ली थी । उसीके जो आंकड़े हैं, वे मैं आपको दे रहा हूं । इससे आप अनुमान लगा सकेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या वास्तव में भार अधिक पड़ेगा या सरकार को बचत होगी । उत्तर प्रदेश में सरकार जो राशि सहायता के रूप में उन स्कूलों को देती है वह 9 करोड़ 68 लाख है । जो फीस के द्वारा पैसा एकत्रित होता है वह 9 करोड़ 5 लाख होता है । यानी कुल मिला कर 18 करोड़ 73 लाख यह हो जाता है । ये सरकारी आंकड़े हैं जो कि आपके कागजात में भी सुरक्षित हैं । मैं कोई नए आंकड़े नहीं दे रहा हूं । अब लीजिये, व्यय की स्थिति । माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को जो वेतन दिया जाएगा वह 11 करोड़ 42 लाख बैठता है । एड-हाक भत्ता जो दिया जाएगा वह 1 करोड़ 6 लाख है । इस प्रकार से कुल मिला कर और जो

ज्यादा आदमी इस काम के लिए रखने पड़ेंगे और उन पर भी जो बारह लाख रुपया खर्च होगा उसको भी मिला कर कुल खर्च 16 करोड़ 11 लाख बैठता है। आपके यहां पर जमा होगा 18 करोड़ 73 लाख और आप देंगे 16 करोड़ 11 लाख। इस तरह से आपको नैट इनकम 2 करोड़ 62 लाख की होगी लेकिन आप यह कहते हैं कि सरकारी खजाने में पैसा देने में आपके ऊपर अधिक भार पड़ने वाला है। समझ में नहीं आता है कि ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपके पास भेजे हैं या नहीं भेजे हैं? या उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र के शिक्षा मंत्रालय को बिल्कुल अंधकार में रखे हुए है। जिसके आधार पर इस प्रकार का वक्तव्य देकर आप सदन में भी आलोचना का विषय बनते हैं और उत्तर प्रदेश में भी आलोचना का विषय बनते हैं।

आखिर इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि उत्तर प्रदेश में आज भी, इस कमर-तोड़ महंगाई के जमाने में कुछ इस प्रकार की कातिल और जुल्मी प्रबन्ध समितियां हैं, जो अध्यापकों के हस्ताक्षर तो पूरे वेतन पर करा लेती है और वास्तव में उनको बहुत कम वेतन देती हैं। इससे विवश होकर अध्यापकों को अपनी दर्दभरी आवाज उठानी पड़ी है। इस स्थिति में मैं चाहता हूं कि सरकार इस समुचित मांग को स्वीकार करे, जिसको दो राज्य सरकारें स्वीकार भी कर चुकी हैं, और अध्यापकों के असंतोष को बढ़ने से रोके।

जहां तक समान वेतन सम्बन्धी मांग का प्रश्न है, कुछ दिनों पहले लखनऊ में संसद् की सलाहकार समिति बैठक में मैंने उस मामले को उठाया। वहां पर सरकार की ओर से हमें यह जानकारी दी गई कि इस पर 1,67 लाख रुपया अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है, अगर अध्यापकों को सीधे सरकारी खजाने से पेमेंट की जाये, तो 2,62 लाख रुपये की सेविंग होगी। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के बजट पर अतिरिक्त भार पड़ने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है?

एक सवाल यह भी है कि अगर आपकी सरकार के स्थान पर कल किसी दूसरे दल की सरकार आ जाये तो उसे पहले किये गये निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पहली सरकार ने 7 अगस्त, 1967 को विधान परिषद् में यह घोषणा की थी कि हम समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं कि उसके बाद राज्यपाल को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वह उस सरकार के निर्णय की इस प्रकार धज्जियां उड़ायें और उसको कार्यान्वित न करें।

मैंने इस प्रश्न को नैनीताल में संसदीय सलाहकार समिति में भी उठाया। वहां पर मुझे यह जानकारी दी गई:

> "पिछले वर्ष से उक्त अध्यापकों को उन्हीं दरों से महंगाई भत्ता मिलने लगा है, जो उनके समकक्ष अध्यापकों को राज्य सेवा में मिलता है। इस प्रकार उक्त अध्यापकों की उपलब्धियां अन्य राज्यों के अध्यापकों की तुलना में लगभग समान ही हैं।"

महंगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया था।

प्रश्न यह है कि आखिर यह मामला कहां रुका हुआ है। क्या इन अध्यापकों के सिर में खुजली मची हुई है जो वे यह आन्दोलन कर रहे हैं? मंत्री महोदय हमें जानकारी दें कि वास्तविकता क्या है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोठारी आयोग की सिफारिशों के हिसाब से वेतन दिये जाने पर 2.05 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ता है। यह कोई बहुत बड़ी राशि

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

नहीं है । यह रुपया व्यय करने से केवल बी० टी० और एल० टी० अध्यापकों की समस्या का समाधान ही नहीं होता है, बल्कि जे० टी० सी० और दूसरे वर्गों के अध्यापकों की समस्या का भी समाधान हो जाता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने कोठारी आयोग बनाया और उस पर लाखों रुपये व्यय किये । अगर उस ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करना है, तो ऐसे आयोग बनाने का लाभ ही क्या है ? देश-विदेश के शिक्षा विशारदों का जो कमीशन बनाया गया, उसने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने सुझाव दिये । अब उन सुझावों को क्रियान्वित करना सरकार का कर्तव्य है ।

एक मांग यह भी की गई है कि जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतनमानों को सुधारा जाये । शिक्षा मंत्री को ज्ञात ही होगा कि जे० टी०सी० अध्यापक को दो वर्ष की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जब कि बी० टी०, एल० टी० अध्यापक को केवल एक वर्ष की ट्रेनिंग करनी पड़ती है । लेकिन आज भी जे० टी० सी० अध्यापक का वेतनमान 60 रुपये वेतन और 44 रुपये महंगाई भत्ता अर्थात् कुल मिला कर 104 रुपये से शुरू होता है और 120 रुपये वेतन तथा 62 रुपये महंगाई भत्ता अर्थात् कुल मिला कर 182 रुपये पर अन्त होता है । इस की तुलना में उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अधीनस्थ चपरासी का वेतनमान 111 रुपये से प्रारम्भ करती है । इन्टरमीडिएट और मैट्रिक ट्रेन्ड जे० टी० सी० अध्यापक का वेतन 104 रुपये और चपरासी का वेतन 111 रुपये ।

अगर बेचारा जे० टी० सी० अध्यापक बी० ए० या एम० ए० भी पास कर ले, तो भी उसके वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी । हां, यदि वह अपनी पुरानी सोनियारिटी को खत्म कर दे और अपनी वर्तमान संस्था को छोड़ कर किसी नई संस्था में काम करे, तो वह कोई लाभ उठा सकता है । मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर जे० टी० सी० अध्यापकों की इस मांग में क्या अनौचित्य है ।

जहां तक स्कूलों में काम करने वाले क्लर्कों का सम्बन्ध है, आप को यह सुन कर दुःख होगा कि 1947 से लेकर आज 1968 तक उनके लिए कोई सेवा के नियम नहीं बनाये गये हैं । आज भी उन्हें केवल 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है और उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल, मेनेजर या सैक्रेटरी की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है । इस देश में बेरोजगारी के शिकार युवकों को इस कमर-तोड़ महंगाई में इतने अल्प-वेतन पर काम करने के लिए विवश होना पड़ता है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति भी दयनीय है । इसलिए सरकार को तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को निर्धारित करना चाहिए ।

मुझे यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि जब उत्तर प्रदेश के अध्यापकों ने हड़ताल और सत्याग्रह के अन्तिम हथियार का सहारा लेना चाहा, उस समय सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया । हालांकि उन के आन्दोलन में हिंसा की गंध तक नहीं थी और तोड़-फोड़ का आभास तक नहीं था । जहां तक अध्यादेश जारी करने का प्रश्न है, जब कभी इस देश को पाकिस्तान के साथ संघर्ष में उतरना पड़ेगा, उस समय शायद राष्ट्र-द्रोही तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ेगा । ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ही अध्यादेश जारी करने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए । लेकिन अध्यापकों के विरुद्ध अध्यादेश अगर इस प्रकार अध्यादेश की धज्जियां उड़ाई गईं, तो एक दिन वह आयेगा, जब सरकार के कानून महत्वहीन हो जायेंगे । इसलिए

अध्यादेश जारी करने के संबंध में मंत्री महोदय को सावधानी बरतनी चाहिए ।

इस समय मैं प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की चर्चा न करके एक बहुत बड़ा अन्याय करूंगा । कुछ दिनों पहले सदन में उन के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी । आज उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं के प्राथमकि स्कूलों के अध्यापकों को इस कमर-तोड़ महंगाई में भी वेतन तथा महंगाई भत्ता मिला कर केवल 80 रुपये मिलते हैं । इस स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार कर क्या रही है ?

खेर कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि हर एक राज्य सरकार अपनी आय का 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करे और उस में 10 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करे । अगर उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अपनी आय का 10 प्रतिशत व्यय करती, तो आज प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को कोई कठिनाई न होती । इस समय वह प्राथमिक शिक्षा पर केवल 6 प्रतिशत व्यय करती है । अगर वह खेर कमीशन की सिफारिश के अनुसार उस पर 10 प्रतिशत व्यय करने की व्यवस्था करे, तो उसे 14 करोड़ रुपये मिल जायें । उस स्थिति में, मैं समझता हूं, डा० त्रिगुण सेन को केन्द्र की ओर से 7 करोड़ रुपये देने में कोई आपत्ति नहीं होगी । उत्तर प्रदेश को यह 21 करोड़ रुपया मिलने के बाद इन गरीब अध्यापकों की समस्या उलझी हुई नहीं रह सकती है ।

आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई श्रेणियां बनी हुई हैं । हमारे यहां ये चार प्रकार के स्कूल चलाये जा रहे हैं । जिला परिषद् तथा नगरपालिका के स्कूल, पब्लिक स्कूल, कनवेन्ट और मिशनरी स्कूल, मान्टेसरी स्कूल । इन स्कूलों के शिक्षा के स्तर और पद्धति में जमीन आस्मान का अन्तर है । यह केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि सारे देश की समस्या है । श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में, जिस में डा० त्रिगुण सेन भी उपस्थित थे, यह निश्चय किया गया था कि शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए इस प्रकार के भयंकर अन्तर को समाप्त किया जाय । परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । यदि सरकार ने वास्तव में इस देश में एक समाजवादी समाज की रचना करनी है, तो उस को शुरूआत वहां पर करनी चाहिए, जहां से मस्तिष्क की बुनियाद पड़ती है ।

आज देश में, और विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में, शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आ गई है, उसका एकमात्र कारण है अध्यापकों का असंतोष, जिसकी छाया या प्रतिच्छवि, छात्रों में भी देखने को मिलती है ।

अभी तक अध्यापकों का आन्दोलन राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलनों से पृथक् है । परन्तु मुझे खतरा है कि अगर अध्यापकों के हितों और उन की मांगों की बराबर इसी प्रकार उपेक्षा होती रही, तो कहीं अध्यापक भी किसी राजनैतिक पार्टी की गोद में न जा पड़ें । जो उन का दुरुपयोग करे । देश के भविष्य के लिए वह स्थिति बड़ी खतरनाक होगी । इस लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अध्यापकों और छात्रों को राजनीतिज्ञों के चक्कर में पड़ने से बचायें, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें और राष्ट्र-निर्माण में शिक्षकों के योगदान को प्राप्त करें ।

अन्त में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । एक तो उत्तर प्रदेश की इस भयंकर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और शिक्षा मंत्री, डा० त्रिगुण सेन, को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दूसरे, अगर सरकार ने राष्ट्र-निर्माता गुरु को कारावास का दरवाजा न दिखाया होता, तो भविष्य के लिए वह एक बड़ी स्वस्थ परम्परा होती। लेकिन जो भूल हुई, सो हुई। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाये, तो कोई बात नहीं है। जो शिक्षक इस समय जेल में हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाये, ताकि वे अपने घरों में वापिस आयें और राष्ट्र-निर्माण के काम में लग जायें। तीसरी मांग यह है कि उत्तर प्रदेश जिस के संबंध में आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि देश भर में सब से कम वेतन यहां के अध्यापकों को मिल रहा है। रोज-रोज यहां पर यह चर्चा का विषय न बने। रोज-रोज उन को आंदोलनों का सहारा न लेना पड़े। इसलिए भविष्य के लिए कुछ इस प्रकार की स्थिर योजना बनाइए ताकि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को भी उसी प्रकार वेतन मिल सके जिस प्रकार से पंजाब के अध्यापकों को मिल रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा के अध्यापकों को मिल रहा है। वह भी इस कमर-तोड़ महंगाई के जमाने में अपना पेट भर सकें और अपने बच्चों का पेट भी भर सकें।

श्री शिवनारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, मैं श्रीमान् का बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने ऐसे पवित्र अध्यापकों के कार्य के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रकाशवीर शास्त्रीजी का अनुगृहीत हूं, उन्होंने बड़े आंकड़े दिए, लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। तीन अरब रुपये का यू० पी० का बजट रहा है अगर उसका दस परसेन्ट इनके ऊपर खर्च करते तो 30 करोड़ रुपया आपका खर्च होता। 3 अरब में से 30 करोड़ खर्च कर देते तो यह सवाल नहीं उठता। उत्तर प्रदेश भारत की वह तपोभूमि है जिसने राम और कृष्ण दिए, जिसने कबीर को दिया जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और हिन्दू यूनिवर्सिटी को दिया, और मान्यवर, भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का श्रीगणेश अगर कहीं से हुआ तो वह उत्तर प्रदेश से हुआ। सन् 42 के मूवमेंट का बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी केन्द्र रहा। भारत में जो त्याग और बलिदान है उसका आदर्श है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों ने जो आजादी की लड़ाई में सहयोग किया था वह इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार को भूलना नहीं चाहिए। मैं मांग करता हूं डा० त्रिगुण सेन से कि आप अध्यापक रहे हैं.....(**व्यवधान**).....जरा बोलने दीजिए मौलाना साहब-

तमीजे न वासत कमन्दे हवा ।
उलटने को रोटी उलट दी तवा ।।

अध्यक्षजी, एक अध्यापक बोल रहा है और यह लोग बोलने नहीं देते हैं। कहा है :

कुंभकार: भूमी तिष्ठति
सादण्डेन चक्रं भ्रामयति ।

अध्यापक कुंभकार है भारत का। भारत का नव निर्माण करता है। डा० त्रिगुण सेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं प्रिंसिपल रहे है, शिक्षा शास्त्री हैं आप से कोई बात छिपी नहीं है। यह जो मैनेजिंग कमेटियां हैं यह इतनी वर्स्ट हैं, मैंने चागला साहब को प्वाईन्ट आउट किया कि तुम हिंदुस्तान की शिक्षा को नेशनलाइज कर दो। जितनी फीस बच्चे देते हैं और जितना गार्जियन देते हैं और जितना आप देते हैं उससे बढ़िया तरीके से यह चल सकते हैं और डिसिप्लिन मेन्टेन हो सकती है। इन गुरुजनों के साथ, मैं कहना चाहता हूं, अगर चपरासियों जैसा बर्त्ताव करोगे तो तुम्हारी औलाद चपरासी पैदा होगी, राम और कृष्ण पैदा नहीं कर सकोगे। तो यह जो आंकड़े

हैं यह हिसाब रखो, अपनी ट्रेजरी में भेजो। यह सारे मैनेजमेन्ट फेल हो जाएंगे । सारे षडयंत्र का अंत हो जायगा ।

लेकिन मैं अध्यापकों से एक अपील करना चाहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज से वह दूर रहें.... (**व्यवधान**)....मैं किसी विदेशी के सहारे नहीं हूं । मैं भारती हूं और मैं भारत सरकार का रक्षक हूं..... (**व्यवधान**).....अध्यक्ष महोदय, मैं बाराबंकी से नहीं आता हूं जहां कत्ले आम होता है। अध्यापक लोग गैलरी में बैठे हैं आपका नमूना देख रहे हैं राम सेवकजी । होश में रहिए ।

मैं एक अपील कर रहा हूं गवर्नमेंट से कि जो हिसाब किताब है अध्यापकों का वह गलत नहीं है, मुनासिब मांग है, उचित मांग है। जैसा मैंने कल कहा था, मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से कहा और होम मिनिस्टर थे तीनों बैठे थे, शिक्षा मंत्री नहीं थे, आजाद साहब थे, लेकिन मैं इस वक्त शिक्षा मंत्री से कह रहा हूं कि इन गुरुजनों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। इन्हें जेल-खानों से रिहा कीजिए । सुदामा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं हुआ है। सुदामा की स्त्री जब कहती है सुदामा से :

द्वारका जाहु जू, द्वारका जाहु जू

तो सुदामा कहते हैं :

शिक्षक हूं सिगरे जग को ताकहं

तू अब देति है शिक्षा ।

हमारे शिक्षक वर्ग सुदामा जैसे शिक्षक आज भी देश में मौजूद हैं। बैनर्जी साहब कान खोल कर सुन लें। इन के भाई भी प्रोफेसर हैं। (**व्यवधान**)

हमारे भाई अध्यापक बैठे हुए हैं, वह देख लें विरोधी दल का नमूना । उनकी-वकालत कर रहा हूं और यह बोलने नहीं दे रहे हैं ।

SHRI S. M. BANERJEE: We are not supposed to mention who is sitting in the gallery,

श्री शिवनारायण : इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं पत्रकारों से भी अपील करूंगा कि इनके नक्शे देख लीजिए । कितना जेनुइन काम हम कर रहे हैं देश के लिए मांग कर रहे हैं और यह इनका नमूना है । मैं अध्यापकों से कहूंगा कि इनके जाल में वह न आएं ।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : यह माध्यमिक शिक्षक संघ के बारे में बोल रहे हैं या सबके बारे में बोल रहे हैं ?

श्री शिवनारायण : प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब का मैंने कहा । मैं रेप्रेजेन्ट करता हूं अध्यापक समाज को पार्लियामेंट के अन्दर और गुमान के साथ कहता हूं । मुझे कोई हेठी नहीं है इसको कहने में और सरकार से लड़ने में कोई हिच-किचाहट नहीं है । मैं मांग कर रहा हूं कि उनकी जितनी मांगे हैं वह मांगें पूरी की जायं । इन शब्दों के साथ मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि डा० त्रिगुण सेन इन की मांगों को मानेंगे और शिक्षकों को कल रिहा कर देंगे ।

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : The basic cause behind the present agitation in my mind is the failure of the country to evolve any uniform system of education all over the country. There are different rules for appointment, there are different scales of pay, there are different curricula and in every respect there is a differnet system in different States. Sometimes we doubt whether in the matter of education there is any unifying factor in the country. Now, out of this process, the new phenomenon has arisen, the agitation by the teachers. The hon. Minister said while

[Shri D. N. Patodia]

replying to the previous debate that they expect discipline from the teachers. They expect that they demonstrate in a disciplined manner. May I remind him that discipline is a two-way traffic and not a one way traffic ?

The Kothari Commission's recommendations were made more than 2 years ago. Why are these people agitating ? Nobody wants to agitate. The fact that section of the society which is known for its sobriety, for its discipline—it has never agitated before in the history of the last 20 years since Independence—all of a sudden start this agitation, means that there is something wrong in our educational system. They have waited for more than 2 years. They have made all sorts of representations and they had to resort to this particular weapon against their own wish and against their own liking. Now, as my friend, Shri Prakash Vir Shastri said, what is their pay ? In Secondary Schools they get Rs. 104 in U. P. and in the Primary Schools they get Rs. 80, lower than the pay of a chapprassi, lower than the level of subsistence. No Indian can live a decent life with this meagre amount of salary. Still we expect that while he is not capable of subsisting himself he should be disciplined, he should not agitate and he should not do anything and they should accept all the dictates from the Administration, whichever way he likes.

We clamour that the standard of education should go up. We clamour that we should reach the level of the international standard of education. By keeping the teachers dissatisfied in the manner we are doing, we drive the calibre out of this profession and in this manner we cannot expect any higher standard of education. How can we blame the students for their enthusiasm when we are not capable of taking care of the teachers by providing their minimum needs of substistence and how can we clamour that we will be able to get the calibre out of them when we are not capable of retaining the talent in the teaching profession. That is what is being done. Now when 8000 teachers have been arrested and the strike is going on for the last 10 days, there are no signs of settlement. They are making representations to the Central Government, to the Prime Minister and the Education Minister. God knows what will be the result.

SHRI S. M. BANERJEE : They met the Prime Minister.

SHRI D. N. PATODIA : One of the arguments that is put forward by the Government and the hon. Education Minister is paucity of funds.

I do not understand how any such argument can have any validity whatsoever. We do not have paucity of funds to waste crores and crores of rupees on our administration. The Public Accounts Committee and various Commissions have come to the conclusion that all sections of our administration are wasteful; we are wasting our money. We do not have paucity of funds for setting up the Bokaro Steel Plant, but we have paucity of funds for providing the minimum standards of subsistence to the teachers. Therefore, any such plea which is given to the effect that we do not have funds and so we cannot pay cannot hold good. This is one of the basic necessities if this country has to develop; if we have to arrive at higher standards of education, if we have to create discipline in the system of education, we have to provide not only what the Kothari Commission has recommended but much more than that.

We have to see that the best calibre is retained in the educational system. If we are not able to do that, all your work, all the reports of your Commissions, all that you do will be absolutely futile. Do not waste your energy. Do not waste the funds in setting up Commissions. If you do not implement the recommendations which run to hundreds of thousands of pages, there is no sense. Therefore, look at this from the point of view of what is necessary, what is desirable, whether the demands of the teachers are reasonable and are minimum demands. If they are, you must find out the ways. Whether it is the Centre or the States, it makes no difference. A man living in India, on the soil of India, as an Indian, has to get his minimum needs fulfilled, and the Central Government which is a unifying factor in

the country is responsible to see that a teacher gets the minimum that is needed by him.

With these remarks, I want to make three suggestions in support of what Shri Prakash Vir Shastri said. I must congratulate Dr. Triguna Sen for having taken a bold step in trying to evolve a system which will ultimately unify the educational system of the country. But I am a little sorry to say, as I find from newspapers, that the fourth Five Year Plan allocations are likely to be reduced in respect of education. This would be the most disastrous thing to be done in this country. You can cut any other allocation, you can do whatever you like with regard to industry, to the, economy, with regard to any other thing but take care of your education. Education should have its proper place today. The educational allotments must not be reduced at any cost, and if you do that, it will be at the cost of your national standards, at the cost of your standard of education. The level of your society will go down.

I also support what Shri Prakash Vir Shastri said, that all the teachers who have been arrested must be released immediately. You have to create an atmosphere under which all can talk freely across the table and under which they feel that they are not being humiliated. Whether it is the Central Government or the State Government, it makes no difference. In any case, Uttar Pradesh is under President's rule at the moment, and therefore, nothing should be left to the local authorities, and the Central Government must interfere to see that something is settled with the least possible delay.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, आज क्या विडम्बना है कि जिस वर्ग पर सारे भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी है, जिस वर्ग के हाथ में सारे देश की बागडोर सम्भालने वाले नवयुवकों का निर्माण करने की जिम्मेदारी है, जिस वर्ग के हाथ में विद्या, धर्म, हमारी पुरानी संस्कृति और अनुशासन जैसी चीजों की जिम्मेदारी है, आज वही विवश होकर, दर-दर की ठोकरें खाकर, लोक तन्त्र का जो अन्तिम अस्त्र है—स्ट्राइक, उसको हाथ में लेकर, उठा हुआ है—यह बड़ी चिंता का विषय है और मैं आपसे कहूंगी कि इसके पीछे जो दर्दनाक कहानी है, उसको हम और अधिक टाल नहीं सकेंगे। आज इस सदन में जितनी पार्टियां हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर, कम-से-कम शिक्षकों के मामले में एक होकर आज हम लोग राष्ट्र का आवाहन करें और अपने शिक्षक वर्ग से अनुरोध करें कि जो अन्तिम अस्त्र उन्होंने अपने हाथ में लिया है, उस अस्त्र को वे इस्तमाल न करें तथा उस अस्त्र का इस्तेमाल न कराने के लिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि उनको आश्वासन दे कि उनकी जितनी भी उचित मांगें हैं उन पर शीघ्र-से शीघ्र विचार करके उनका विश्वास प्राप्त करे।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अगर सरकार न करे तो वे क्या करें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार क्यों नहीं करेगी, जब जनता की आवाज उठी है तो वे उसकी आवाज को जरूर मानेंगे।

श्री रवि राय (पुरी) : ये कहेंगे कि रुपया नहीं है।.....[व्यवधान]...

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह शायद आप कहने वाले हैं, मैं मानने वाली नहीं हूं।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जब हमारे शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं यह बात स्वेच्छा से कही है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है, जब सरकार स्वयं इस बात को महसूस कर रही है तो क्या कारण है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और आप क्यों इस अन्याय को टालते जा रहे हैं ?

मैं आपसे पूछना चाहती हूं—मेरे पास सरकारी आदेश की एक प्रतिलिपि है उससे

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

स्पष्ट होता है कि जब वहां संविद की सरकार थी, उसने एक आदेश जारी किया था—यह आदेश 15 नवम्बर, 1967 का है—जिसमें कहा गया था कि इनकी मांगों पर सभी पक्षों द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत राज्यपाल महोदय ने आज्ञा प्रदान की है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जुनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को 1 अगस्त, 1967 से उसी तरह का महंगाई भत्ता दिया जायेगा जिस तरह उसी स्तर के राजकीय शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। मान्यवर, इस पर शायद सरकार की तरफ से यह कहा गया है—मैंने राज्य सभा की प्रोसिडिंग्ज से पढ़ा है—कि इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। यह आश्वासन केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में था, इसमें शिक्षक वर्ग शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगी इस आदेश की सत्य-प्रमाणित प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। इसमें क्या तथ्य है, इसकी वास्तविकता से हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

दूसरी बात—जब छागला साहब हमारे शिक्षा मंत्री थे, सुना जाता है कि उस समय केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 48 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया था और यह कहा गया था कि उस धनराशि से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को किसी न किसी तरह की राहत दी जायगी। मैं जानना चाहती हूं कि उस रुपये का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को किस प्रकार उस धनराशि से सहायता मिली। मैं चाहती हूं कि आप हम को बतायें कि इस के सम्बन्ध में वास्तविक परिस्थिति क्या है ?

तीसरी चीज आज हर बात के लिये यह कहा जाता है कि शिक्षा एक स्टेट सब्जैक्ट है, इस लिये केन्द्रीय सरकार की इच्छा होते हुए भी वह अपना सक्रिय कदम नहीं उठा सकती। म जानना चाहूंगी कि इस में क्या दिक्कत है इसको कान्करेंट सब्जेक्ट क्यों नहीं बना दिया जाता ? हमेशा के लिये इस विडम्बना को, इस अन्याय की जड़ को हटाने में क्या दिक्कत है ? मैं यह भी जानना चाहूंगी—कि आप आल इण्डिया एजूकेशन सर्विस की तरह की कोई चीज क्यों नहीं बना सकते ? देश भर में जो समान कार्य करने वाले लोग हैं उन को समान वेतन दिया जाये यह मेरी मांग है और मेरा ख्याल है कि शिक्षा मंत्री महोदय जो स्वयं एक बहुत उच्च स्तर के शिक्षा शास्त्री हैं और जिनको शिक्षकों से पूरी सहानुभूति है, वह इस पर विचार करेंगे तथा आल इण्डिया एजूकेशन कैडर बना कर जो समान कार्य करने वाले लोग हैं उनको समान वेतन देने की मांग को अवश्य स्वीकार करेंगे।

हमारे सामने कुछ ऐसी शिकायतें भी आई हैं जैसे फैजाबाद का एक केस मेरे सामने आया है, जिसमें एक अध्यापक को हस्ताक्षर करने के लिये 24 घन्टे तक बन्द कर के रखा गया। कुछ अध्यापकों को दो वर्षों से लेकर 6–6 माह का वेतन नहीं मिला है.....

MR. CHAIRMAN : She should conclude in two minutes.

SHRI S. M. BANERJEE : We can sit till 7 O'clock. The minister may be called after 6 O'clock.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जब ऐसी शिकायतें हमारे सामने आई हैं कि शिक्षकों को दो वर्षों से लेकर 6–6 माह का वेतन नहीं मिला है, तो सरकार आश्वासन दे कि उन शिक्षकों को एक माह के अन्दर या दो माह के अन्दर वह वेतन दिलवायेगी तथा जितनी भी अनियमिततायें हुई हैं उन सब को दूर करके ऐसी

व्यवस्था करेगी जिस से सब को समय पर वेतन मिले । जो ऐसा नहीं करते हैं उनके खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिये. जिन संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार की अनियमितायें बरती गई हैं और शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिला है, उनके साथ सख्ती बरती जाये ताकि भविष्य में वे इस प्रकार का कार्य न कर पायें ।

सभापति महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमारे सामने आया है, जिसकी बहुत सी चीजें हमारे सामने आ रही हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर प्राहिविशन के लिये जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है—मैं प्राहिविशन को माननेवाली हूं और सख्ती से माननेवाली हूं—अगर प्राहिविशन को कार्यान्वित करने के लिये हमारे वित्त मंत्री महोदय ने एक साहसिक कदम उठाया है कि कुछ वर्षों के अन्दर हम सारे देश में प्राहिविशन को लागू करेंगे, तो मैं जानना चाहती हूं कि शिक्षा, जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो हमारी रोजी, रोटी और जिन्दगी का मसला है, जिस पर हमारा भविष्य निर्भर है, क्या कारण है हमारे वित्त मंत्री उसके लिये शिक्षा मंत्री राज्यपाल के साथ, शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ तथा योजना आयोग के साथ बैठकर कोई योजना क्यों नहीं बनाते ? वह ऐसी कोई योजना बनायें, कि कुछ वर्ष के अन्दर, दो तीन वर्ष के अन्दर जब लोकप्रिय सरकार बन जाती है तो कदम-ब-कदम इस तरह की चीज लागू करेंगे । और मेरा विश्वास है कि इस प्रकार से वित्तीय सहायता देने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट होने के उपरान्त, इस तरह की चीज लागू हो जाये ।

चौथा पोइंट यह है कि योजना आयोग के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों को 10 प्रतिशत सहायता दी जा रही है । मेरा कहना है कि जो चार प्रदेश कोठारी कमीशन की संस्तुतियों को कार्यान्वित नहीं कर पायें हैं उन चार प्रदेशों के लिये कुल धनराशि अलग से रखी जाये जिस से सारे देश में शिक्षा का स्तर एक समान हो सके और जो एक इमबेलैंस है वह समाप्त हो सके । अगर पेट में ज्वाला है उस को आप किसी तरह का आदर्श नहीं सिखा सकते । अगर हम इस ज्वाला को नहीं बुझा सकेंगे तो हम समस्या का निराकरण नहीं कर सकेंगे । इसलिये योजना आयोग से शिक्षा मंत्री कहें कि वे चार प्रदेश जहां पर कोठारी कमीशन की संस्तुतियों का कार्यान्वियन नहीं हो रहा है उनको अलग से वित्तीय सहायता दी जाये ।

एक माननीय सदस्य ने धनाभाव की बात कही । मैं उसको मानने वाली नहीं हूं । मैं जानती हूं कि अगर दिल में तत्परता और जोश है तो वह काम रुक नहीं सकता है । मेरा माननीय रवि राय तथा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर आज हम सब लोग एक राय हैं कि इस वर्ग को जो स्थान मिलना चाहिये समाज में वह नहीं मिला हुआ है तो हम लोग अपने वेतन में से 10 प्रतिशत कटौती करा कर एक टीचर्स वैलफयर फंड बनायें । यद्यपि यह एक सांकेतिक राशि होगी लेकिन हम उनका विश्वास प्राप्त कर सकेंगे कि हम उनकी मांग को स्वीकार करते हैं ।

टीचर्स से भी एक बात कहना चाहती हूं । शुरू-शुरू में उन्होंने कहा था कि केवल डेढ़ महीने का हमारा एजीटेशनल प्रोग्राम रहेगा और पहली दिसम्बर को समाप्त कर देंगे । और साथ ही यह भी कहा था कि राजनीति के बीच में नहीं आयेंगे । 9 तारीख के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो छपा है उससे क्या जाहिर हो रहा है । उस में छपा है कि:

> "Mr. Thakurai, the acting President of the Secondary School Teachers today, *i. e.*, on 9th December, said that the government's antipathy towards their reasonable demands might force them even to boycott the High Schools and Intermediate Board Examinations."

मान्यवर, आप के माध्यम से मैं शिक्षक वर्ग से अनुरोध करूंगी एक बहन और मां होने के नाते कि आज अगर वे इस तरह का

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

कार्य करेंगे तो हमारे लाखों की तादाद में बच्चों का भविष्य बरबाद हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि अगर सरकार उन की जायज मांगें मानती है, और हम सब सदस्य उन की बातें मनवा दें, कुछ थोड़ा त्याग करके, तो कोई कारण नहीं है कि जेल के द्वार, जो डाकुओं और चोरों के लिये होते हैं, वे हमारे गुरुजनों के लिये हों।

MR. CHAIRMAN : Mr. Kundu.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Mr. Chairman, nobody has spoken from Jan Sangh side.

MR. CHAIRMAN: I have got here the time taken by your Party on the Banaras Hindu University discussion. Your Member has taken more time and that has been deducted here. You have got only one minute at your disposal.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : That was a different debate. Mr. Chairman, this has never happened before that the time taken in one debate is deducted in another debate. Our Party's view-point also on this issue must be placed before the House.

MR. CHAIRMAN: You must cooperate with me. 4 hours have been given for the same Ministry. We must keep to the timing. You should have seen to it that your Member did not take so much time on Banaras Hindu University discussion. You have got only one minute.

SHRI NARAIN SWARUP SHARMA (Dowasiaganj) : Sir, no member has spoken from the Jan Sangh on this subject.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The previous speaker was speaking on the Banaras Hindu University debate.

MR. CHAIRMAN : Since both relate to the Education Ministry, they should have been careful to see that they do not exceed the time allotted to their groups.

SHRI NARAIN SWARUP SHARMA : We want the Jan Sangh point of view on this specific issue to be placed before the House.

MR. CHAIRMAN : Let me see. I have already called Shri Kundu. He should be brief.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Mr. Chairman, today we find that the future makers of our younger generation are behind the prison, rotting for days together, nobody is hearing their case and nobody is treating them even with sympathetic words. It was said that a delegation of the teachers met the Prime Minister and the Prime Minister, as usual, with her cryptic smile, did not say anything as to how she is going to relieve the woes of the suffering teachers. I am really shocked to know that even the teachers have to go on strike, face lathis and dandas of the police for the redressal of their grievances.

When the SVD government in Uttar Pradesh was dissolved, it was about to implement some of the assurances for removing the grievances of teachers. It was hoped that during the President's Rule at least the demands of the UP teacherst would be sympathetically considered. Bu nothing was done. For days together we have been demanding this in Parliament House, taking out groups of people and meeting the authorities. Yet, nothing has come out of it and there has not been even a positive reaction.

The other day Shri Morarji Desai was saying in Goa that if prohibition is somehow introduced throughout the country he will find Rs. 200 crores for meeting that expenditure. The demands of the UP teachers is to bring in parity in their pay scales which will need about Rs. 1 crore to 2 crores. Yet, government say that they are not able to find this money.

I do not want to go into the details of the Kothari Commission Report. As Shri Sen himself has said, it is shocking that the salary of a teacher is less than that of a constable. We have been told that we must give due consideration, due honour and prestige to the teachers who

are going to build the future of our younger generation. Every year we bring some of them to Delhi make a fanfare and present them with National awards. But, at the same time, what type of social status do we give to them ? In our country a person who is working as a peon, a police constable, a chaprassi or menial, he has no status; he belongs to an under-priviledged class for years. The difference in ratio of salary of different classes of employees in government is sometimes 1:1000. Under these circumstances, if we want to give them a due share and a real status in society, we have to improve their economic lot. The day of giving lip sympathy and saying "we are sympathetically considering it" are over. Now the time has come when Government have to come out and say what exactly they are going to do.

I am not sorry that the teachers have organised a strike and in furtherance of their demand have defied the law non-violently and have courted arrest. To me it gives a lot of hope because this depressed class of the people is realising its rights and its strength and is trying to organise itself. A day will come when they will force this Government, the people who run the destiny of the country, to realise their demand because in their demand there is justice. Once you deny this justice, there is bound to be upheaval, ferment, turmoil. Therefore, whatever nice words we might say, if we are not going to improve their lot, I think, there is a grim future awaits our younger generation and for all of us, I should say.

The Kothari Commission has recommended that as a interim measure they should be paid Rs. 100 as a minimum pay immediately. This much even the Government has not been able to implement. In UP the Government has said that they are one of the lowest paid primary teachers of India. Let the Government come out with an assurance, a categorical assurance. Let us know from the Education Minister what step exactly they have taken inside the Government to put forth the case of these primary teachers for which we have been fighting for days together. Let him say that he has been fighting for this and has been demanding this but the other people in the Cabinet are blocking it and are not giving it. Let him make out a case that he has been demanding more money in the Budget year after year but the other people in the Government are not coming forward and giving the money. He does want to say that. He says that there is no money. Money has to be found out and this process of strikes, organised movement, organised non-violent movement, will see that these people find out the money for this under privileged of employees of the Government of India.

It is time we must have a look at the planning. After 21 years of this administration, what sort of priority are we going to five in the planning and how much money are we going to put in the planning for the welfare of students, for the welfare of teachers, for better living conditions of primary, secondary and other teachers?

In Asia, forget about the world, our *per capita* expenditure on education is one of the lowest. If you see the statewise break-up, in many backward States, it is one of the lowest in the world. If you want to maintain democracy, if you want that democracy should really be vibrant, a really living organisation, you must see that the poeple are educated quickly. It is a shocking and alarming thing to find that today 70 per cent of the people, according to Government statistics, in the rural areas are still illiterate and uneducated. And these poor, humble, dumb people, the real people of India, have so far maintained this democracy when democracy in other parts of Asia has fallen and the lamp is being put out! In such circumstances if you do not take strides within 5, 6 or 10 years, if you do not make out a scheme, plough back more money, stop wasteful expenditure and give them their due, their right to the teachers, the future of the country is dark. It is not an isolated case of UP teachers. It will be more shocking to find, it will be a really sorrowful fact when lakhs of primary teachers go on strike demanding an increas in their basic wage from Rs. 83 to Rs. 150. Therefore to avoid such a catastrophe, I would request the Education Minister and also the Prime Minister—fortunately, the the Prime Minister is here—that both of them should come out with something concrete and positive and not just reply mechanically to Members because they have to reply.

[Shri S. Kundu]

I would request you to create a better climate. These teachers should be released forthwith. The aparity in their pay-sclaes should be fulfilled. They should not be given only a lip assurance. The hon. Minister should give an assurance here saying that he is immediately taking steps to release certain amount of money to increase their minimum pay-scales, to increase their D. A. and to improve their other conditions.

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा (हमीरपुर) : सभापति जी, समाज में अध्यापकों का एक विशेष स्थान है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। अध्यापकों का मामला इस सदन में कई बार आया और कई बार उस पर विचार हुआ तथा विचार के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उन बातों पर विशेष ध्यान भी दिया और उन्होंने कुछ ठोस कदम भी उठाए। उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, मैं एक हकीकत की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और वह हकीकत यह है कि जितने भी सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं सभी उन अध्यापकों से कुछ सीख कर, कुछ बन कर यहां पर आए हैं। यह हमारी जो कौम है उसकी बुनियाद स्कूलों और कालेजों में बनती है।.. (**व्यवधान**).. हमारा देश अच्छा बने, हमारी कौम अच्छी बने, यह सारी-की-सारी जो बात है इसके लिए शुरू शुरू में या तो माता-पिता कुछ कर सकते हैं या फिर उसके बाद हमारे अध्यापक कुछ कर सकते हैं। हमारा देश अच्छा बने, यह बात अध्यापकों पर ही निर्भर करती है कि वे देश को कैसा बनाते हैं। इस बात से आप इत्तफाक करेंगे कि भूखे-पेट कोई भी अच्छी बुनियाद नहीं बना सकता है। भूखा पेट इंसान दीवारों में रेता ही चुनेगा, सीमेंट या बजरी नहीं लगायेगा और जब रेत की दीवारें होंगी तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे मजबूत हो सकता है, इस बात का अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसके साथ ही आज जो सफेदपोश लोगों की फौज तैयार हो रही है, वे कुछ करना तो चाहते नहीं हैं, केवल झगड़ा-फसाद ही करना चाहते हैं। उनके कारण अनुशासनहीनता ही बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि उनको ठीक तरह से और ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दी गई। और ठीक ढंग से और ठीक तरह से शिक्षा तब तक नहीं मिल सकती है जबतक कि शिक्षा देने वालों के पेट में पूरी रोटी न हो। आज अध्यापकों को चपरासियों से भी कम तनख्वाह मिलती है, एक पुलिस के सिपाही से भी कम तनख्वाह मिलती है, एक क्लर्क से भी कम तनख्वाह मिलती है, जबकि एक अध्यापक के काम में और एक क्लर्क के काम में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को जब अध्यापक लोग देखते हैं कि एक आदमी जो क्लर्की करता है या चपरासी का काम करता है वह हमसे ज्यादा तनख्वाह पाता है तब वह इस बात को कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, अध्यापकों के साथ एक अन्याय और भी है। एक प्रदेश के अध्यापकों की एक तनख्वाह, दूसरे प्रदेश के अध्यापकों की दूसरी तनख्वाह और तीसरे प्रदेश के अध्यापकों की तीसरी तनख्वाह, जैसे हरियाणा में अध्यापकों की एक तनख्वाह है, पंजाब में दूसरी तनख्वाह है और हिमाचल प्रदेश में तीसरी तनख्वाह है। एक प्रदेश से जो तीन अलग-अलग प्रदेश बने हैं उन तीनों प्रदेशों में टीचर्स की अलग-अलग तनख्वाहें हैं। इस बात पर भी टीचर्स झगड़ा करते हैं, हड़ताल करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, साथ के एक प्रदेश में ज्यादा तनख्वाह है लेकिन हमारी कम है। अध्यापकों के असन्तोष का एक यह भी बहुत बड़ा कारण है, जिसकी तरफ मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री जी ने पूरा ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूं सारे शिक्षकों की तनख्वाह लगभग एक जैसी होनी चाहिए, कम-से-कम

जो साथ के प्रान्त हों उनमें तो एक होनी ही चाहिए।

अभी यहां पर कुन्डू जी ने यह कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उपद्रव होंगे। दूसरी ओर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा है अनुशासन के मुताल्लिक, कि विरोध करने की कला सीखें। उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं कि विरोध करने का आर्ट सीखें। विरोध करने के लिए भी आर्ट की जरूरत है, कला की जरूरत है, लेकिन उस आर्ट को, उस को सिखाये कौन? उस कला को तो हम सिखाते नहीं हैं। उनको तो हम केवल किताबें रटाते हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं होता है। कैसे अनुशासन कायम किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, जब उनको बताया जायेगा तभी तो वे जानेंगे। तो जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा, उनको पहले हम वह कला सिखायें। वह कला सीखने की व्यवस्था पहले खुद करें तभी यह बात बढ़िया हो सकती है।

17 hrs.

इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा और वैसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब लोग हड़ताल करते हैं या हुल्लड़बाजी करते हैं तभी सरकार उनकी ओर ध्यान दिया करती है। जब तक खामोशी से वह सरकार से अर्ज करते हैं मंत्री लोगों से अपनी मांगों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उनके सामने जाकर वह अपना केस रखना चाहते हैं तब यह सरकार उन्हें मिलने की इजाजत भी नहीं देती है। जिम्मेदार सरकारी अफसर होते हैं वह मंत्री से मिलने की उन्हें इजाजत नहीं देते है। लेकिन इस तरह से निराश होकर और लाचार होकर जब वह अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और जब वह उनकी अर्थी उठा कर निकलते हैं तब सरकार डर कर चौंकती है और उनसे पूछती है कि भाई क्या मामला है। मेरा कहना है कि सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर वह वैधानिक तौर पर चलते हैं और अपनी मांगों को कायदे से सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार को उनको सुनना चाहिये और वैधानिक तरीका अपनाने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इसके विपरीत जो लोग महज हुल्लड़बाजी करते हैं, गुन्डागर्दी करते हैं उनसे सरकार को ठीक तरीके से निबटना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी करने वालों की किसी भी कीमत में कोई मांग स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं महज चंद एक सुझाव आपके सामने रख कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

1. अध्यापकों की तनख्वाहों के बारे में समय-समय पर जो कमिशन बनाये गये हैं जिनमें एक कोठारी कमिशन भी था, उनकी सिफारिशों को सरकार मान्यता दे। जितने भी पे स्केल की कमिशन ने सिफारिश की है वह पे स्केल उन्हें दे दिया जाय।

2. अध्यापकों की तनख्वाहें आपस में मिलते हुए प्रान्तों में एक ही हों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जिससे अध्यापकों को कोई स्वार्थी राजनीतिक दल या व्यक्ति गुमराह न कर सके।

3. अध्यापकों को तनख्वाहें देने के साथ-साथ स्कूलों के परिणामों के लिए भी कोई मापदंड रखा जाय। यह हम नहीं चाहते कि अध्यापकों की तनख्वाहें तो बढ़ा दी जायें और उनके बच्चे सारे फेल होते रहें। बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी का मापदण्ड सरकार रक्खे और जिन अध्यापकों की पढ़ाई का काम उस मापदण्ड के अनुरूप हो उनकी तनख्वाह

[श्री प्रेम चन्द्र वर्मा]

सरकार बढ़ाये । सरकार इस बात का ध्यान रक्खे कि जिन अध्यापकों की वह तनख्वाह बढ़ाये वह उसके मुताबिक बच्चों की शिक्षा का स्टेन्डर्ड भी ऊंचा ले जा सकें । जब तक पढ़ाई का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारा पैसा जो भी हम देते हैं वह देश और कौम का पैसा खड्डे में जायेगा, नाले और रेते में जायेगा । इसलिए उन टीचर्स के ऊपर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इस देश के बच्चों को ठीक तरीके से तालीम देकर उन्हें इस देश का आदर्श व उपयोगी नागरिक बनायें । इसके लिए मेरा सुझाव है कि जिन स्कूलों या क्लासों के परिणाम 50 प्रतिशत से कम हों उनकी सालाना तरक्कियां रोक दी जाये ।

4. अध्यापकों को जब ट्रेनिंग दी जाती है उस वक्त उन के क्लासों में देश के चोटी के शिक्षा शास्त्रियों की सेवाओं का फायदा उठाया जाना चाहिए ताकि वहां वह अध्यापकों, राष्ट्रीयता, अनुशासन और कर्त्तव्य-पालन का पाठ पढ़ायें । वह अध्यापकों को उनकी जिम्मेदारियों को समझायें ।

5. हिमाचल प्रदेश के टीचरों को फौरन कोठारी कमिशन द्वारा सुझाया हुआ ग्रेड देने की उनकी मांग को भारत सरकार पूरा करे । अगर इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता की मांग करे तो उसे पैसे की भी वह सहायता दे । केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरन्त वहां के अध्यापकों को कोठारी कमिशन के अनुसार ग्रेड देने का परामर्श दे ।

सभापति महोदय, हमें अध्यापकों की समस्या पर गम्भीरता व सहानुभूति से विचार करना है और उन्हें कोठारी कमिशन की सिफारिश के अनुसार वेतन देना है ताकि उन पर जो बच्चों को पढ़ाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है उसे वह योग्यता के साथ निभा सकें । अगर अध्यापकों की दशा नहीं सुधरी, उनके जायज असन्तोष को दूर नहीं किया गया और उनकी समस्या पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो यह देश के लिए एक बड़े खतरे व अहित की बात होगी । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बाकी सभी टीचरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी उनके साथ किसी प्रकार की सख्ती न की जाय और जो अध्यापक कैद में हैं उन्हें छोड़ दिया जाय ।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा (डुमरियागंज): सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात थी कि अभी दो, तीन मिनट पहले यहां पर प्रधान मंत्री महोदया बैठी हुई थीं क्योंकि आज देश में एक ऐसी स्थिति आ गयी है कि यह तो शिक्षकों की बड़ी बात है अगर कोई बहुत छोटी बात भी होती तो भी वह आज प्राइम मिनिस्टर के हस्तक्षेप के बिना न सुधरती । इसलिए अच्छा होता कि इन्दिरा जी अभी बैठी रहतीं ।

आज उत्तर प्रदेश में प्रेसीडेंट का शासन है और वह शिक्षक वर्ग जो सब से अधिक गौरवान्वित वर्ग होना चाहिए था आज जेलों में बन्द किया जा रहा है और वह जेल में यातनाएं भोग रहा है ।

मैं लखनऊ गया था और वहां की डिस्ट्रिक्ट जेल इन अध्यापकों से भरी हुई थी । सेंट्रल जेल में जहां कि दूसरी तरह के साधारण अपराधी कैदी रक्खे जाते हैं वहां पर उन बेचारे अध्यापकों को रक्खा गया था । जहां से 40 मील दूर मेरठ की जेल में 1500 माध्यमिक शिक्षक बंद हैं । जिनमें 87 महिलाएं हैं और 5 बच्चियां भी उनके साथ हैं । यह एक स्थिति है जिसे जानबूझ कर छोटी-छोटी बातों के लिए अध्यापक जो कि एक प्रबुद्ध वर्ग समझा जाता है कभी पैदा नहीं करता है ।

मुझे माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से एक चिट दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि

एक अनट्रेंड ग्रेजुएट की तनख्वाह 84 रुपये है और एक चपरासी की तनख्वाह 105 रुपये है। मगर वाकई यह स्थिति है तो सचमुच में यह इतनी भयंकर स्थिति है कि इमरजैंसी के बेसिस पर इस को टैकिल किया जाना चाहिए।

आज स्थिति जैसा कि मुझे बताया गया केवल यही नहीं है कि उन अध्यापकों की तनख्वाह कम है बल्कि स्थिति यह भी है कि जो भी उनकी तनख्वाह होती है वह भी मैनेजिंग कमेटी के कारण उन को ठीक समय पर नहीं मिल पाती है। माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से दिये गये ज्ञापन से मुझे पता लगा कि केवल अकेले बलिया जिले में 11 लाख रुपया बतौर वेतन के अध्यापकों को अभी दिया जाना बाकी है। ऐसा भी है कि कहीं-कहीं पर अध्यापकों को डेढ़-डेढ़ और दो-दो साल से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं मथुरा गया था वहां पर कुछ शिक्षकों ने मुझे बतलाया कि उन्हें उनका वेतन पिछले डेढ़ साल से नहीं मिला है और अगर वह कहते हैं कि उन्हें उनका वेतन मिलना चाहिए तो उनको धमका दिया जाता है कि कहीं और चले जाओ। ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक बात है कि शिक्षकों का वेतन सरकार के राजकीय कोष से मिलना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति थी जो तुरन्त ठीक हो जानी चाहिए थी। उस समय संविद सरकार के शिक्षा मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त के सामने जब माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से यह योजना रक्खी गई तो उन्होंने उसे तुरन्त मान लिया था। मेरे सामने आंकड़े हैं लेकिन समयाभाव के कारण इस समय मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन यह एक योजना बनाई गई थी कि अगर फीस का 80 प्रतिशत और सरकारी अनुदान मिला कर केन्द्र अपने हाथ में लेकर वेतन बांटे तो इस प्रकार ढाई करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। यह योजना साउंड है यह पुरानी संविद सरकार ने मान लिया था। लेकिन इसके विपरीत यहां हमको यह बतलाया जाता है कि ढाई करोड़ रुपये ज्यादा लगेंगे या और भी अधिक खर्च होगा जबकि उस योजना के अनुसार ऐसा लगता है कि ढाई करोड़ रुपये की बचत थी। यह बात मैंने उत्तर प्रदेश की सलाहकार समिति की नैनीताल वाली मीटिंग में बतलाई थी। वहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव मौजूद थे और उन्होंने इस बात से इंकार किया था कि इस बारे में कोई निश्चय शिक्षा मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त ने किया था। जब मैं श्री राम प्रकाश गुप्त से मिला तो उन्होंने मुझे बतलाया कि यह निश्चित रूप से फाइलों में है कि इस तरह का निश्चय लिया जा चुका था। जब लखनऊ में फिर उत्तर प्रदेश सलाहकार समिति की मीटिंग हुई तो मैंने शिक्षा सचिव के उस झूठ की ओर चव्हाण साहब का ध्यान दिलाया और मैंने चव्हाण साहब से कहा कि इस प्रकार से लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह झूठ बोलना क्यों आवश्यक समझा गया? अब अगर अफसर लोग ज्यादा काम करने से घबड़ाते हैं तो उनको साफ तौर पर कह देना चाहिए कि वह काम नहीं करना चाहते लेकिन जहां पर शिक्षकों के पेट का सवाल हो वहां पर वह इस तरह झूठ बोल दें कि संविद सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय ही नहीं किया था तो यह एक बड़ी आपत्तिजनक बात है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें केन्द्र के शिक्षा मंत्री को तुरन्त कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसा मैंने कहा यह असत्य मैंने चव्हाण जी को बतला दिया है कि तलवार साहब इस बारे में झूठ बोल गये हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने इस बारे में कुछ किया या नहीं। मैं इस बारे में उनसे जानना चाहूंगा।

यह कहा जाता है कि जब संविद की वहां सरकार थी उस समय भी उसने इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया था और अब जब पापुलर सरकार आएगी तभी वह इन मांगों

[श्री नारायण स्वरूप शर्मा]

पर विचार करेगी और तभी कोई निश्चय लेने की स्थिति में वह सरकार होगी। इस समय वहां पर गवर्नर का राज है, इस वास्ते कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि कम से कम दो प्रान्त ऐसे हैं कि जहां पर पापुलर सरकारें न होते हुए भी कोठारी कमिशन की शिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उनको लागू कर दिया गया है और ये प्रान्त हैं बिहार और पंजाब। इस वास्ते उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको इस चीज को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

जहां तक सरकारी खजाने से पेमेंट करने का सवाल है केरल और मैसूर में पहले से ही इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

जहां तक बहुत ज्यादा भार पड़ने की बात का सम्बन्ध है, बहुत ज्यादा रुपया खर्च होने की बात का सम्बन्ध है, मेरा कहना यह है कि अगर शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार दस प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाता तो आज यह स्थिति पैदा न होती कि जिसमें साधनों के अभाव का बहाना किया जाता। मैं समझता हूं कि अब भी आप रुपया खर्च करने की स्थिति में है और कर सकते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को देखें। उनको आप इधर-उधर कर सकते हैं। आप चौथी योजना बना रहे हैं और उसमें आप ढाई अरब रुपया केवल लोगों की नसबन्दी करने पर जो अभियान चलाया जाएगा, उस पर व्यय करने का विचार कर रहे हैं। बारह दिसम्बर को जब शिक्षा मंत्री माध्यमिक संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे तब उन्होंने उनको बताया था कि 84 लाख रुपया डी० ए० में पैरिटी लाने पर खर्च होगा। डी०ए० में पैरिटी की बात को तभी स्वीकार किया जाएगा अगर शिक्षक अपनी एजीटेशन को वापिस ले लें। आप देखें कि कहां यह 84 लाख रुपया और कहां ढाई अरब रुपया जो अकेली नसबन्दी पर खर्च होगा। मैं चाहता हूं कि प्राथमिकतायें जो आपने रखी हैं, उन पर आप पुनर्विचार करें।

मैं अन्त में दो तीन सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसा इंग्लैंड में है बर्नहम कमेटी जैसी एक कमेटी यहां भी बनाई जाए जिसमें सरकार के प्रतिनिधि हों, शिक्षकों के प्रतिनिधि हों। वे मिल बैठ कर शिक्षकों के वेतन स्तरों के बारे में निश्चय कर लें और उसको मान लिया जाए। यह सही है कि शिक्षा प्रान्तीय विषय है। फिर भी मैं चाहता हूं कि शिक्षकों के वेतनों का जहां तक सम्बन्ध है, यह चीज केन्द्र के हाथ में होनी चाहिये और केन्द्र बर्नहम कमेटी जैसी एक कमेटी बनाये।

मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नौ हजार के करीब शिक्षक जेलों में बन्द पड़े हैं उनकी बातों को मानकर उनको तुरत रिहा कर दिया जाए। कम-से-कम उनको निश्चित आश्वासन आपकी ओर से दिया जाना चाहिये कि आप क्या करने जा रहे हैं। डी० ए० की पैरिटी की बात जिसमें 84 लाख का खर्चा आता है, 7 अगस्त 1967 को संविद ने ही मान ली थी। उसके बाद से आप जो धमकियां आदि देते रहे हैं, इनको आपको देना बन्द करना चाहिये। आर्डिनेंस जो आप जारी करते हैं इनके बारे में वह ठीक नहीं है और आर्डिनेंस का यह उचित उपयोग नहीं है। इसका उचित उपयोग आप और कहीं करें। मैं चाहता हूं कि शिक्षकों को आप जेलों में जाकर सड़ने के लिए विवश न करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दो दिसम्बर से सारे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं। पिछले कई बरसों से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में और

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में बहुत असंतोष चला आ रहा है ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के अन्य प्रान्तों में जो स्थिति अध्यापकों की है उनसे बहुत ही गिरी हुई और अत्यन्त ही दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की है चाहे वे प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक हों या माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक हों और चाहे विश्वविद्यालयों के अध्यापक हों । जो मांग इस वक्त उनकी है और जिसको लेकर उन्होंने आन्दोलन करने का रास्ता पकड़ा है, उसमें उनकी दो मांगें मुख्य हैं । एक तो उनकी मांग यह है कि राजकीय विद्यालयों में और अ-राज्यकीय विद्यालयों में शिक्षकों के जो वेतन क्रम हैं, उनमें जो भेदभाव है और महंगाई भत्तों में जो भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए । यह मांग उनकी बहुत ही उचित मांग है और इसको सिध्दांततः स्वीकार भी कर लिया गया है । इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिये । उनकी दूसरी मांग यह है कि सरकारी खजाने से उनको वेतन का भुगतान होना चाहिये ।

यह जो दूसरी मांग है इसको पेश करने के लिए वे क्यों विवश हुए हैं ? उत्तर प्रदेश की एक विशेष स्थिति है । वहां अ-राजकीय विद्यालय व्यापार के अड्डे बने हुए हैं । दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा जगत में चोर बाजारी जिस को कहते हैं अगर वह कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है और व्यापक रूप से है । अध्यापकों की वहां पर ऊंचे वेतन क्रमों पर नियुक्ति की जाती है लेकिन वेतन देने का सवाल आता है तो उनको 50 रुपये या 75 रुपये कम वेतन दे कर पूरे वेतन पर उनके हस्ताक्षर करवा लिये जाते है । उनको अपनी जीविका के साथ समझौता करने के लिये बाध्य किया जाता है । उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, विवश किया जाता है । यह जो चोरबाजारी उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में व्यापक रूप से विद्यमान है, यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है । यह स्थिति अत्यन्त ही निन्दनीय है । इसलिए अध्यापकों की यह जो मांग है कि उनको सरकारी खजाने से वेतनों का भुगतान होना चाहिये, यह बहुत ही उचित मांग है और न्यायसंगत मांग है ।

शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री तथा सभी लोगों ने कहा है कि उनको उनके साथ पूरी सहानुभूति है और वे इसका कोई हल निकालना चाहते हैं । लेकिन यह जो नाटक है यह कई बरसों से चला आ रहा है, इसका कोई हल निकाला नहीं गया है । अब शिक्षकों को मजबूर होकर हड़ताल करने का कदम उठाने पड़ा है जिससे विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, अभिभावक चिन्तित हैं और सारे विद्यालय उत्तर प्रदेश के अन्दर पेरेलाइज्ड हैं । सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 60 प्रतिशत अध्यापक आज हड़ताल पर है । लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत से भी अधिक शिक्षक आज हड़ताल पर है । बहुत से जिले ऐसे हैं कि जहां पर सारे स्कूल बन्द कर दिये गये हैं ।

मैं आपको ग्यारह दिसम्बर की घटना को सुनाता हूं । आजमगढ़ जिले में जब गवर्नर वहां से गुजर रहे थे तो अध्यापकों ने शान्तिपूर्ण तरीके से उनके सामने अपनी मांगें पेश कीं । कहीं किसी ने एक ढेला मार दिया और इसको लेकर अध्यापकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । अध्यापकों के ऊपर लाठी चार्ज, हजारों की संख्या में अध्यापकों को जेलों के अन्दर बन्द करना, इसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है । यह ऐसी चिन्ता की बात है कि हम सबको गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये । मैं भारत सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता । मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश का पिछले बीस बरसों का शासन इस सबके लिए

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जिम्मेदार है। उसने साधन इकट्ठा नहीं किये, अध्यापकों की बात को उसने नहीं माना। उनकी उचित और न्यायसंगत बात को आज तक माना नहीं गया है। आज वहां पर राष्ट्रपति शासन है। आज भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि वह इस समस्या का हल करें। शिक्षा मंत्री चिन्ता तो व्यक्त करते हैं लेकिन कहते हैं कि संविधान ने राज्यों को कुछ अधिकार दे रखे हैं और शिक्षा राज्यों का विषय है और भारत सरकार इसके अन्दर दखल नहीं दे सकती है। जब तक यह समस्या बनी रहेगी, जब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, तब तक यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ-साथ आप देखें कि सदन के चारों तरफ से आज इस चीज को समर्थन मिला है। इस वास्ते आपको इस बात पर फिर से विचार करना चाहिये कि क्या यह उचित नहीं होगा कि एक राउंड टेबल कान्फेंस बुलाकर संविधान में और परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वैसा भी कर लिया जाए ताकि शिक्षा के साथ खिलवाड़ न हो और भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय न हो। अध्यापक समाज के निर्माता हैं। राष्ट्र के निर्माता है। अगर वे भूखे रहेंगे, अगर वे असंतुष्ट रहेंगे, और उनके साथ चोर बाजारी की जाएगी उनकी दयनीय अवस्था को लेकर मजाक और मखोल उड़ाया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिये।

अगर सरकारी खजाने से पैसा उनको दिया जायेगा तो कितना भार सरकार पर पड़ेगा? अभी शास्त्री जी ने इसका हिसाब लगा कर बताया है। उनके जो आंकड़े हैं उनको मैं सही मानता हूं। और सरकार के जो आंकड़े हैं उनको मैं सही नहीं मानता हूं। सरकार जो कहती है कि उस पर एक करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा इसको मैं सही नहीं मानता हूं। अगर सरकारी खजाने से उनको वेतन का भुगतान होगा तो प्रबन्धक जो स्कूलों के हैं वे उनका शोषण नहीं कर सकेंगे और कम पैसा देकर ज्यादा की रसीद नहीं ले सकेंगे, उनकी मजदूरी का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इससे स्कूलों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वेतन उनको ठीक से मिलेंगे। अगर उनको सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो यही मानना पड़ेगा कि जो उनके साथ फ्राड होता है, जो फोरजरी होती है, सरकार उनको मान्यता प्रदान करती है। उस अवस्था में उनको सही वेतन देना पड़ेगा और इस लिए वह समझती है कि उस पर एक करोड़ का भार पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि अगर कोठारी कमिशन की सिफारिशों को मान लिया जाए अगर राजकीय अध्यापकों के वेतन क्रमों को राजकीय अध्यापकों के वेतन क्रमों के बराबर कर दिया जाए तो कुल मिलाकर तीन चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा। यह वार्षिक भार होगा। जिस सरकार का तीन सौ करोड़ रुपये का बजट हो उसके लिए तीन चार करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा भार नहीं है। इससे शिक्षा जगत के अन्दर एक सन्तोष की लहर दौड़ जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकेगा। यह जो उनकी मांग है यह मानने जाने के काबिल है और इसको मान लिया जाना चाहिये और इस बोझ को बरदाश्त कर लिया जाना चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्री से और प्रधान मंत्री से भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हजारों की संख्या में जो अध्यापक जेलों में बन्द हैं उनको तत्काल रिहा किया जाये। वहां के राज्यपाल द्वारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे बात न करना, राष्ट्र के निर्माताओं का तौहीन करना है। उनको वहां पर कह दिया गया है कि शिक्षा सचिव से मिल लो। इसमें कोई तर्क नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनसे

बात करने में भारत सरकार पहल करे। भारत सरकार शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुलाये, उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाये और आवश्यकता हो तो योजना आयोग के प्रतिनिधियों को बुलाये और साधन ढूंढें और अध्यापकों की मांगों को पूरा करे। उनकी जो दो मांगें हैं,उचित है,न्यायसंगत हैं। मेरा पूरा यकीन है कि अगर वास्तव में हमारी उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति है, जैसे कि होनी चाहिये, और उनको पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं जैसा कि हमें होना चाहिये तो इसका हल निकालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसका कोई न कोई हल निकल सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्थिति और बिगड़ने न दें। इसको आप सम्भालें। पूरे देश के अन्दर इस मामले में एकरूपता लायें। अध्यापकों की जो मांगें उचित हैं उनको माना जाए। इस समस्या का समाधान हो। हमारे अध्यापक हड़ताल करना नहीं चाहते थे वे आन्दोलन नहीं करना चाहते थे, वे राजनीति में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, जिसमें कुछ लोग राजनीति के लिए उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें वह अवसर क्यों देती है ? इस सदन में जो वातावरण है, उसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। सब लोग कहते हैं कि अध्यापकों की बात सही है और उनके साथ सब की हमदर्दी है।

मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव सदन में दिये गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान किया जाये। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री सदन में यह अनुरोध करें कि अध्यापक अपना आन्दोलन वापस लें और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर सम्भव कदम उठायें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, सब से पहले मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के अध्यादेश के खिलाफ हिम्मत से हड़ताल की और उन्हें कामयाबी मिली।

आज जिस वक्त हम लोग इस सदन में यह बहस कर रहे हैं, हमारे आठ हजार शिक्षक बन्धु हमारे भाई और बहन जेल में है। जेल में उन पर जो खर्च किया जा रहा है, मैं उसका एक ब्यौरा आपके सामने रखना चाहता हूं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास रुपया नहीं है। महंगाई भत्ते में पैरिटी नहीं मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन आज जेलखाने में एक अध्यापक पर सात रुपये रोज का खर्च हो रहा है। चूंकि आठ हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं, इसलिये उनको जेल में रखने के लिये 56 000 रुपया रोज खर्च किया जा रहा है। अगर उन्हें एक महीने के लिये जेल में रखा गया तो उन पर 1,68,000 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति को जेल में रखने के लिये 210 रुपया महीने भर में खर्च हो जायेगा, लेकिन कोठारी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती है और न ही महंगाई भत्ते में पैरिटी हो सकती है। यह इन्साफ सरकार ने किया है।

मैं शिक्षा मंत्री और श्री भागवत झा आजाद से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे इस समस्या के समाधान के लिये गवर्नर साहब पर निर्भर करेंगे और शिक्षकों का सारा भविष्य उन्हीं पर छोड़ देंगे, तो यह मसला कभी हल नहीं हो सकता है। जब प्रधान मंत्री और मंत्री महोदय के इशारे पर माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव से मिलने के लिये गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कोई सरकार की तरफ से बात करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ शिक्षा विभाग की तरफ से बात करने आया हूं।

[श्री स० मो० बनर्जी]

शिक्षकों की तरफ से एम० पीज० को जो मेमोरेंडम दिया गया है, उसमें कहा गया है :

"We agreed to negotiate on the 12th under the impression that the Government representatives will be vested with full powers to take decisions on behalf of the Government but the Education Secretary at the very outset informed us that his authority was confined to the Education Department alone and not the Government of U. P."

जब आज सुबह जब हमारे बन्धुगण लखनऊ से यहां आकर प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले, तो प्रधान मंत्री को किसी ने कह दिया कि जब तक संघ की सब मांगें स्वीकार न कर ली जायें, तब तक वह किसी भी बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। यह बिल्कुल गलत और भ्रामक बात है। प्रधान मंत्री के दिमाग को खराब करने के लिये ऐसा किया गया है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि गवर्नर साहब के रवैये से कुछ नहीं हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में जब एस० वी० डी० गवर्नमेंट थी, तो उसने कुछ आश्वासन दिये थे और कुछ सहूलियतें प्रदान की थीं। लेकिन उन आश्वासनों को भी पूरा नहीं किया गया। अगस्त के महीने में सब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया गया, लेकिन शिक्षकों को नहीं दिया गया। आज उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि वह सिर्फ पैरिटी देने के लिए तैयार है।

उत्तर प्रदेश में कुल 56,000 माध्यमिक शिक्षक हैं, जिनमें से 8,000 आज जेल में हैं। तकरीबन 99 प्रतिशत शिक्षक हड़ताल पर हैं। अगर सरकार समझती है कि अध्यादेश के अन्तर्गत शिक्षकों को जेल में बन्द कर देने से हड़ताल खत्म हो जायेगी, तो मैं देश के प्रधान मंत्री, गृह-मंत्री और शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह हड़ताल खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी और जब तक सब-के-सब 56,000 शिक्षक जेल में नहीं चले जायेंगे, तब तक यह आन्दोलन चलता रहेगा। इस समय वहां पर कोई एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकती है। मैं कोई धमकी देने की गर्ज से यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं यह बात किसी राजनीतिक मकसद से नहीं कह रहा हूं। आज शिक्षक जेलखाना देख चुके हैं और एक-साथ जेल की रोटी खा चुके हैं। इसलिए उनका एका, उनका फौलादी इत्तिहाद, कायम रहेगा, जब तक कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर दिया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद ने कहा कि उन्होंने गवर्नर से बात की है कि शिक्षकों को रिहा कर दिया जाये और एक फेअरवेल एटमास्फियर क्रीएट किया जाये। जिस दिन वह बात कही गई, उस दिन एक हजार शिक्षक गिरफ्तार थे, जब कि आज आठ हजार से ज्यादा शिक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं।

जैसा कि श्री शास्त्री ने कहा है, शिक्षकों को ट्रेजरी के द्वारा पेमेंट करने से सरकार को 2,62 लाख रुपये की बचत होगी। इस लिए सरकार को शिक्षकों की उस मांग को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने मेमोरेंडम में यह भी कहा है :

"The UP Madhyamik Shikshak Sangh submits that the Government has already issued a Government Order permitting the managers to appoint JTC teachers with five year's standing in the CT scale of pay and that it is a serious anomaly that a JTC teacher of five years' standing who should be eligible for a higher scale if he gets a fresh appointment in some other

institution, but if he prefers to continue in the same institution he will never be eligible to that grade. We, further submit that it is only the question of amending the said State Government Order by substituting the word "entitled" in the place of the words "eligible for direct recruitment."

उस जी० ओ० की कापी मेरे पास है । मैं उसको सदन-पटल पर रख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं ।

कहा जाता है कि छः करोड़ रुपये की जरूरत है । शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर 2,05 लाख रुपया मिल जाये, तो उनका भला हो सकता है । पहले प्राइमरी टीचर्ज यहां पर आये थे और उन्होंने धरना दिया था । वह एजूकेशन मिनिस्टर से भी मिले थे । आज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि पार्लियामेंट के इन्साफ का दरवाजा खटखटाने के लिए आये हैं ।

मैं चाहता हूं कि अगर श्री मोरारजी देसाई आज सदन में होते, तो अच्छा होता । उन्होंने गोआ में कांग्रेस के सेशन में कहा था कि जो सूबे मद्य-निषेध योजना को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे, वह उनको 50 परसेंट सबसिडी, 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपया, देने के लिए तैयार हैं । इसका अर्थ यह है कि वह नाजायज शराब बनाने और बेचने वालों, बूटलेगर्ज, को सपोर्ट करने के लिए सौ, डेढ़ सौ रुपया दे सकते हैं, लेकिन स्टार्विंग टीचर्स को, जिनके बाल-बच्चे भूखे हैं, जिन के तन पर कपड़ा नहीं है, जिन को दो वक्त रोटी नहीं मिलती है, उन शिक्षकों को, जिन्हें देश-निर्माता कहा जाता है, वह दो या ढाई करोड़ रुपये नहीं दे सकते हैं ।

आज जरूरत इस बात की थी कि प्रधान मंत्री इस सदन में कुछ कहतीं, जिन के इन्साफ के दरवाजे को शिक्षकों ने आज सुबह खटखटाया था । मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह विवशता की हालत में न रहें, वह यह न कहें कि मैं हैल्पलेस हूं । आज उत्तर प्रदेश में कोई एसेम्बली नहीं है; आज वहां पर राष्ट्रपति का शासन है । एस० वी० डी० गवर्नमेंट ने जो फैसला किया था, उस की अवहेलना की गई है, उसका पालन नहीं किया गया है । अब शिक्षक इन्साफ के लिए किस के पास जायें ?

शिक्षकों की पहली मांग यह है कि महंगाई भत्ते के मामले में फौरन पैरिटी ग्रान्ट की जाये ।

जहां तक ग्रेड्ज का प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार जे० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड 150–250 रुपये होना चाहिए, जब कि गवर्नमेंट स्कूलों में उनका ग्रेड 100–180 रुपये और प्राईवेट स्कूलों में 60–120 रुपये है । इसी तरह कोठारी आयोग के मुताबिक सी० टी० टीचर्ज का ग्रेड 150–250 रुपये होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में वह ग्रेड 120–250 रुपये और प्राईवेट स्कूलों में 75-200 रुपये है । कोठारी आयोग के अनुसार ट्रेन्ड ग्रैजुएट का ग्रेड 220–400 रुपये होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में वह 150-350 रुपये और प्राईवेट स्कूलों में 120-300 रुपये है । यही स्थिति पोस्ट-ग्रैजूएट टीचर्ज की है । क्या देश के निर्माताओं के साथ ऐसा व्यवहार करना शर्म की बात नहीं है ?

इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि डी० ए० के मामले में फौरन पैरिटी दी जाये । अगर इस के लिए ढाई करोड़ रुपये की जरूरत है, तो केन्द्र सरकार की तरफ से वह राज्य सरकार को फौरन दिया जाना चाहिए । जब मद्य-निषेध योजना के लिए सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपये पानी की तरह बहाये जा सकते हैं तो शिक्षकों के लिए ढाई करोड़ रुपये भी दिये जा सकते हैं । ताकि हमारे टीचर्स जो हैं जेलखाने में, जो भूखे हैं उनकी भूख मिट सके ।

उसके बाद जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए उनको फौरन छोड़ा जाय ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं डा० त्रिगुण सेन से जो स्वयं अध्यापक हैं, वह मिनिस्टर बाद में हैं, पहले अध्यापक हैं, उन से निवेदन करूंगा कि वह हिम्मत करके जिस तरीके से उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में फैसला किया उसी तरीके से एलान करें इनके लिए भी। आज खाली हमदर्दी से काम चलने वाला नहीं है, केवल आंसू बहाने से काम चलने वाला नहीं है, वह एलान करें कि अध्यापक जेलों से छोड़े जाएंगे। कोठारी कमीशन की रेकमेंडेशन के अनुसार 2 करोड़ 5 लाख रुपया केन्द्र दे। और डी० ए० के मामले में पैरिटी होगा। इनकी बातों को गवर्नर न माने तो मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे गवर्नर को जो आर्डिनेंस के जरिए टीचरों की हड़ताल को कुचले जब कि ला एण्ड आर्डर सिचुएशन बिलकुल लोएस्ट एब पर हो, ऐसे गवर्नर को वहां बिलकुल नहीं रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति जी, यह जब चाहे सदन के बाहर या भीतर शिक्षकों की बात आती है तो यह कहा जाता है कि यह शिक्षक बहुत ही पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, पवित्र कार्य में लगे हुए हैं और भावी कर्णधारों की नींव, उसकी जड़ मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन मैं साथ ही कहूंगा कि जितना बुरा बर्ताव शिक्षकों के साथ हो रहा है शायद और किसी के साथ नहीं हुआ होगा। वेतन को आप छोड़ दें, उनकी सुविधाओं को छोड़ दें, केवल आदर और सम्मान की ही बात लें तो जो प्रारंभिक शिक्षक हैं, जो माध्यमिक शिक्षक हैं इनके साथ इतना अनुचित और अपमानजनक बर्ताव होता है कि जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब आप ने यहां पर घोषणा की कि राज्यपाल महोदय के यहां बातें होंगी, इनकी मांगों पर ध्यान से विचार होगा, सहृदयता से विचार किया जायगा तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ और ठीक से बात हो नहीं चली। एक यह तार आया है वाराणसी से जिसमें यह है कि 76 अध्यापकों को घसीटा गया, घसीट-घसीट कर के उनको जेलों में ठूंसा गया। यह अध्यापकों के साथ हो रहा है और यहां सारे सदन में बैठकर के एक आवाज से मांग कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो, उनकी मांग पूरी की जाय। मैं कहना चाहता हूं कि सदन के किसी व्यक्ति ने किसी दल ने कहीं पर दो राय नहीं बताई। जहां तक कि उनकी मांगों का प्रश्न है। उनकी चार मांगों को मैं दोहराना नहीं चाहता। सब लोगों ने उनको अलग-अलग करके बताया है। यहां तक कि हमारे साथी शिवनारायण जो कांग्रेसी हैं, टिकिट का भी डर रहता है, लेकिन टिकट की भी चिन्ता उन्होंने नहीं की और इसका समर्थन किया। तो इस तरह से उसका समर्थन हुआ। लेकिन केवल मौखिक समर्थन से काम चलने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इस चीज का हल निकाले तो पहला काम यह सोचना चाहिए कि तत्काल सारे अध्यापक जो गिरफ्तार हैं जेल से उनको छोड़ा जाय। आठ हजार अध्यापक आज गिरफ्तार हैं। किसी भी राजनैतिक दल के सत्याग्रह में उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले 5-6 वर्षों में 8 हजार लोग जेल नहीं गए और यह वह लोग हैं कि जिनकी जेल में जाने की आदत नहीं है। लेकिन जैसी कि कहावत है, मरता क्या न करता ? मजबूर हैं भूख से, परेशानी से, इसलिए वह गए। और आज दिक्कत क्या है ? मैंने सुना शायद मंत्रीजी ने कहा कि वह अनसोशल सोशलिस्ट हैं। तो मैं कहूंगा कि अब सोशल सोशलिस्ट बन जायें, अनसोशल नहीं रहें।

मैं निवेदन करूंगा कि इस मुल्क में हिस्सेमारी चल रही है। प्रारंभिक शिक्षक,

माध्यमिक शिक्षक, इनका काफी हिस्सा मारा जा रहा है। इनका हिस्सा मार रहे हैं हमारे देश के बड़े अफसर लोग। उनकी तनख्वाह को और वेतन-क्रम को देखिए तो वह लोग हिस्सा मार रहे हैं। जब तक हिस्सेमारी को आप खत्म नहीं करिएगा, समाजवादी सिद्धांत को चलाइएगा नहीं, तब तक यह कहां से पैसा आएगा? पैसा नहीं मिलेगा। यह रोज शिकायत बनी रहेगी। हिस्सेमारी को खत्म करिए। छोटे कर्मचारियों का, छोटे अध्यापकों का हिस्सा बड़े लोग मार रहे हैं। जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मैं मिलेगा चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के जब श्री गोपाल रेड्डी साहब सर्वेसर्वा बन गए तो वहीं के ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने अपनी सुख-सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की है। एक तरफ अफसर अपने वेतनों में और अपनी सुख-सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करें और दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग वेतन के लिए अपनी मांग लेकर जाते हैं तो उसके लिये इन्कार करें यह कहां तक मुनासिब है? कहा जाता है कि अनुशासन टूट रहा है। विद्यार्थी अनुशासन तोड़ रहे हैं लेकिन अध्यापक जो अनुशासन पढ़ाते हैं वह क्यों तोड़ रहे हैं? केवल इस बात को कह कर के कि अनुशासन तोड़ रहे हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं इस चीज को आप खत्म नहीं कर सकते। जो बुराई है जड़ में उस पर आपको जाना पड़ेगा। कोठारी आयोग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे कम वेतन प्रारम्भिक शिक्षा में लगे शिक्षकों का है। उसके बाद फिर जे० टी० सी० का है और फिर माध्यमिक शिक्षक में और विश्वविद्यालय में जमीन आसमान का अंतर है। और यहां एक तो प्रारंभिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय इनका अंतर, फिर सरकारी और गैर-सरकारी का अन्तर और चौथा अन्तर क्या कि कागज पर कुछ मिले और असलियत में कुछ मिले और फिर जो मिले वह भी कभी तीन महीने तक बाकी रहे, कभी चार महीने तक कभी साल भर तक बकाया रहे। इसके लिए मांग करें तो उनको जेल में ठूंस दिया जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्यों है? जब प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहते हैं कि इतना दो तो मंत्री महोदय कहेंगे कि हम तो 80 प्रतिशत देने के लिये तैयार हैं लेकिन 20 प्रतिशत स्टेट वाले जुटाएं और 20 प्रतिशत वह नहीं जुटाते हैं तो हम कैसे दें? तो यह तो बहुत सुन्दर तरीका है। जानकर आप कहते हो कि वह जुटा नहीं रहे हैं इसलिए हम दे नहीं रहे हैं। इस तरह आप दानी भी बन जाएंगे और अपनी जेब का पैसा भी नहीं जायेगा। तो ऐसे दानी न बनिए। पहले तो जो आपको देना है वह दीजिए, वह देते हैं या नहीं देते हैं इसका इंतजार न करिए। क्योंकि फिर यह मिथ्या बात हो जाती है और बिलकुल बेमतलब की बात हो जाती है। कोठारी आयोग ने क्या कहा कि प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और विश्वविद्यालय में एक दो तीन का अनुपात होना चाहिए वेतनों में। लेकिन अनुपात है एक और 30 का। क्यों बिठाते हैं यह सब आयोग? इन आयोगों के गठित करने का उद्देश्य क्या होता है और इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता? कुछ समय पहले विश्वविद्यालयों के भी कुछ अध्यापक लोग आए थे और उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो रुपया दिया और सुझाव दिया वेतनक्रम का अगर उसको ही लागू कर देते तो उसमें बजाय इसके कि कुछ अतिरिक्त पैसा खर्च होता शायद एकाध लाख रुपया बच जाता। लेकिन यह भी नहीं हो रहा है। तो इन नीतियों के बनाने से क्या मतलब है?

इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि वह तत्काल प्रतिष्ठा के प्रश्न से ऊपर उठें। हर चीज में राजनीति न देखें। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं होती है। सबके

[श्री राम सेवक यादव]

अलग-अलग ढंग होते हैं समस्याओं के हल निकालने के। इसलिए प्रतिष्ठा के प्रश्न से ऊपर उठिए और शिक्षकों की इन चार जायज मांगों को पूरा करिए। उसके लिए अगर आप हिस्सेदारी को खत्म करें तो अधिक पैसा भी लगाना नहीं पड़ेगा और लगाना भी पड़े तो मैं कहूंगा कि सदन बैठ करके उन पैसे के लिये विचार कर सकता है। कहीं दूसरे खर्चों में कटौती हो सकती है। उनके लिये पैसा दिया जा सकता है। इन सब बातों को कहते हुए मैं यह कहूंगा मंत्री महोदय से कि गुड़ी-गुड़ी बात ही कह कर के इस मामले को खत्म मत कर दीजिएगा। कुछ आश्वासन दीजिएगा, कोई हल निकालिएगा। 1965 में भी यह हड़ताल हुई थी। अगर आप यह सोचते हो कि वह दब जाएंगे तो यह मत समझिएगा कि हमेशा दबे रहेंगे। वह फिर उठेंगे। इसलिए इसका कोई हल निकालिए।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : माननीय सभापति जी, इस समय ऐसे प्रदेश के अध्यापकों के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है, जहां आबादी बहुत है, राजनीति बहुत है, किन्तु वहां की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है और इसके कारण जो भी आशायें हमारे शिक्षक लोगों की हैं, चाहे वे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकगण हैं, चाहे माध्यमिक विद्यालयों के या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकगण हैं, वे आशायें पूरी नहीं हो रही हैं।

लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। यदि किसी सरकार ने उनकी दशा सुधारने का प्रयास किया, प्रयास ही नहीं किया बल्कि उनकी नौकरियों में स्थायित्व लाई, उनकी अनेकों असुविधाओं को दूर किया, उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि की तो वह कांग्रेस की सरकार थी।

जो महानुभाव उत्तर प्रदेश के हैं या अन्य प्रदेशों के हैं मैं उनको बतला दूं कि जहाँ वह एक तरफ प्रबन्ध समितियों के सम्बन्ध में अनेकों बातें कह रहे हैं—वहां की कांग्रेस सरकार ने उस प्रदेश की प्रबन्ध समितियों को इस तरह से बना दिया है कि जो कुछ भी वे करें, वह शिक्षकों के हित में ही कर सकती है, लेकिन अगर कोई अनुशासनहीनता हो या और कोई गलत काम होता है तो वे उसको रोक नहीं सकती है। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि जो भी गैर सरकारी संस्थायें है, गैरसरकारी प्रबन्ध समितियां है, उनके हाथ में अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे वे बनाने के बदले कुछ बिगाड़ सकें। मेरे उन साथियों को इस बात की जानकारी ही जानी चाहिये। लेकिन यह सही है कि वहां के अध्यापकों की हालत बहुत खराब है—सरकारी अफसरों या जो बड़े या छोटे रोजगारी है उनके मुकाबले अध्यापकों की दशा बहुत शोचनीय है। मैं अधिकृत रूप से जानता हूं कि बहुत से माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के अध्यापकों का तो उस वेतन में महीना भर खर्च भी नहीं चलता, उनको उधार लेकर खर्च करना पड़ता है। हमें उन से पूरी सहानुभूति है। विरोधी दल के लोगों की तरह से सिर्फ मौखिक सहानुभूति नहीं है, बल्कि हम पहले भी जो वहां मंत्री होते थे जब कांग्रेस के मंत्री आये तब भी और आज भी मंत्रियों के पास जाकर बातचीत करते हैं और समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करते हैं।

जब रुपया देने की बात आती है-तो मुझे कुछ आश्चर्य होता है, इस तरह से इस सदन में बात की जाती है जैसे इस सदन के पास रुपयों का कोई खजाना रखा हुआ है और कोई उसे दे नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है। रुपया आयेगा कर से, टैक्स लगा कर, आमदनी को बढ़ाकर रुपया आयेगा और इसके लिये मैं कांग्रेस बेंच की तरफ से कहता हूं कि टैक्स लगाकर भी अगर माध्यमिक, प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दशा सुधर सकती है तो अवश्य सुधारा जाय और उनकी मांगों को पूरा किया

जाय। यह बात मैं यहां ही नहीं कह रहा हूं बल्कि सीधे जनता के सामने जाकर, वहाँ चुनाव के मैदान में भी कह सकता हूं कि कर लगाया जाय और उनकी हालत को सुधारा जाय। लेकिन यह सिर्फ केन्द्रीय सरकार द्वारा दे देने की ही बात नहीं है, हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार मदद करे, जहाँ से भी पैसा मिल सके उसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, यदि शिक्षा के लिये कृषकों पर भी कर लगाना पड़े, तो हम उसके लिये भी तैयार हैं–इस बात को हम आगामी चुनाव में भी कहने के लिये तैयार है।

सभापति जी, मैं प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, लेकिन रुपया तो जनता से ही आयेगा, किसानों से आयेगा, मजदूरों से आयेगा, उपभोक्ताओं से आयेगा, तभी उन मांगों की पूर्ति हो सकती है, सत्याग्रह से या जेल जाने से यह पूर्ति नहीं हो सकती, इस सम्बन्ध में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से ही पूर्ति हो सकती है।

MR. CHAIRMAN : Shri Viswanatham. Only three minutes.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I happen to be a member of the Uttar Pradesh Consultative Committee. I, therefore, expect not only my two minutes but another two minutes also.

MR. CHAIRMAN : As a matter of fact, you do not have any time at all left.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) : But you can give our time.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : I have no claim. All right, please give me ten minutes.

MR. CHAIRMAN : I request you to conclude in three minutes.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Although the problem of teachers has been raised in connection with Uttar Pradesh, the problem is a common problem throughout the country. All the teachers, particularly of the lower grades, are suffering in the same way. But that does not mean that you should not give special attention to Uttar Pradesh.

Our Government has got a special knack of creating problems. They create problems of students by making them frustrated. They create problems for the non-gazetted and all Government officers by passing an Ordinance. They also create problems for the teachers, Not only do they create problems but they also put them in the jail. Why do you put them in jail?

Now, I want this Government to start with a clean slate from today. Will the hon. Minister make a determination in his own mind that from today, from this minute, he should start something new in this country? How long shall we have all these disturbances, all these strikes and all these imprisonments ?

What is that these people have done? They have extracted sympathy of every section of the House because they have carried on their strike in a very non-violent way. You all say 'non-violence'; you are a lover of non-violence. Even if you want to punish those who have done some-violent act, caught in the act, why don't you have sympathy for those who are non-violent? Why don't you show your sympathy and express it by releasing them at once, here and now?

I am told when the teachers met the Prime Minister, the Prime Minister smiled. Some said, it is usual for her to smile....

SHRI S. M. BANERJEE : That had effect only for 3 hours, not more than that.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Let her smile a little more and a little more and it will have a longer effect. In Order to show her sympathy, she came here. It was token sympathy for she sat for a few minutes only.

[Shri Tenneti Viswanatham]

I want the Prime Minister and the Education Minister to create some peace in this country. Let them start even if the Home Minister is not able to start. Why not the Education Minister take the credit of starting peace in this country?

After all, these teachers are very poor people starting with Rs. 84 only as in other States also. How do you ask them too live? I see, from the Memorandum and the speeches made by hon. Members from every side of the House that they have the sympathy of all. Why? it is because they are in real, hard and grievous circumstances.

You talk about resources. As my hon. friend has said, you are spending Rs. 211 crores for family planning. You want this country to have no children at all and, then, the problem of education will be solved, there will be no teachers and the problem will be solved? No, you take away Rs. 2 crores out of Rs 211 crores allocated for family planning. There is the ready money there. In fact, I think, the Planning Commission has provided Rs. 211 crores as a cushion like that to meet an emergency. You take money out of that and satisfy the teachers. As everybody has said, it is through teacher, your and my children come into the public life and it is they who will become the citizens after us and it is they who must rule this country.

My appeal to you is to create a calm atmosphere and steal a march over the Hom Minister. I am asking the Education Minister to do that.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : How?

SHRI TENNETI VISWANATHAM : By releasing the imprisoned teachers at once.

श्री सत्यनारायण सिंह (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं अध्यापकों की सारी मांगों का समर्थन करता हूं तथा अपने उन तमाम मित्रों के साथ सहमत हूं, जिन्होंने शिक्षकों के सम्बन्ध में अपने विचार यहां प्रकट किये हैं।

समय नहीं है, परन्तु एक बात की ओर मैं अपने शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूं। आप इस बात को देखिये कि इस हाउस के अन्दर सभी सदस्यों ने—चाहे विरोधी पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के हो—उनकी मांगों का समर्थन किया है तथा यदि आप देश में भी देखें, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अन्दर वहां भी उनकी मांगों का बहुमुखी समर्थन किया जा रहा है। ऐसी हालत में आज हमारा प्रजातन्त्र इस पार्लियामेन्ट के अन्दर जिसमें विरोधी और सरकारी पक्ष दोनों की एक राय है—उनके समर्थन में है। अब आप इस को लागू करते हैं या नहीं आप के कन्धों पर यह बहुत बढ़ी जिम्मेदारी पार्लियामेन्ट ने डाल दी है। मुझे उम्मीद है आप इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जो कुछ शिक्षक कह रहे हैं, उनको इस तरह का आश्वासन देंगे कि जिससे आज जो दयनीय स्थिति है, जो और ज्यादा बिगड़ने जा रही है, उसको रोकने में सक्षम हो सकेंगे तथा लोगों की आशाओं को पूरा करने में मददगार साबित हो सकेंगे

श्री शिंकरे (पंजिम) : सभापति जी, मैं भी शिक्षक था, मैंने 11 साल तक अध्यापन किया है और मैं जानता हूं कि शिक्षकों की क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या मजबूरियां होती हैं, मैं जानता हूं उनकी क्या कमजोरियां हो सकती हैं और मैं यह भी जानता हूं कि उन का क्या सामर्थ्य हो सकता है। सभापति जी आपके जरिये से मैं मंत्रिमंडल को एक बात बताना चाहूंगा कि जो गोआ में हो रही थी। आप जानते होंगे कि स्वातंत्र्य के बाद गोआ में एक स्ट्राइक हुई अध्यापकों की, जो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक थे। पहले जमाने में, पोर्चुगीज जमाने में अध्यापक जो मराठी-शालाओं के थे वह खाजगी थे। वहां सरकारी मराठी शालायें नहीं चलती थीं। लेकिन

आजादी के बाद आप जानते हैं वहां शालायें हो गयीं मराठी माध्यम की और वे शालायें सरकारी क्षेत्र में चलीं गयीं। जब यह प्रश्न आया कि खाजगी क्षेत्र में जो शिक्षक काम करते थे उनको सरकारी क्षेत्र की शालाओं में लिया जाय तो जो मिलिटरी गवर्नमेंट वहां की थी और उसके बाद आई० सी० एस० लोगों की गवर्नमेंट आई उन्होंने ऐसा फैसला किया कि जो शिक्षक खाजगी क्षेत्र में हैं उन को सरकारी क्षेत्र की शालाओं में नहीं लिया जायगा। जिसके कारण वहां स्ट्राइक हुई, और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। हम लोगों ने गोआ में महाराष्ट्रवादी गोमान्तक नाम की संस्था स्थापित की थी और वह यही चाहती थी कि वहां की भाषा मराठी है इसलिये गोआ का महाराष्ट्र में मर्जर हो। हम लोगों को यह अध्यापकों का स्ट्राईक का मौका मिला, साथ ही हजारों असंतुष्ट आदमी मिल गये। वे शिक्षक सामर्थ्यवान थे। परिणाम क्या हुआ? आप जानते हैं कि वहाँ पर पहले चुनाव में कांग्रेस की हन्ड्रेड परसेन्ट डिफीट हो गई, उसको एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो। वहां जो 8 हजार शिक्षक हैं, उनकी जो मांगें हैं उन का समाधान न हो? और वे असंतुष्ट रहें? मैं चाहता हूं कि शिक्षक और विद्यार्थी पौलिटिक्स में न आयें। लेकिन मजबूर होकर वे आ सकते हैं और पौलिटिक्स में आने के बाद, जैसे कि गोआ में कांग्रेस को सो प्रतिशत डिफीट हुई ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। जो लोग इस बार चुनाव में जीतकर यहां संसद में आ गये, वे आ सकेंगे क्या नेक्स्ट इलेक्शन में? मैं जानता हूं शिक्षक की बड़ी शक्ति होती है, गोआ में उनकी सामर्थ्य का प्रभाव पड़ा। इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षकों की जो कठिनाईयां हैं उनको सरकार ध्यान में रखे और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करे।

पिछले हफ्ते में गोआ में ए० आई० सी० सी० का अधिवेशन हुआ जिसमें मोरार जी देसाई ने यह आश्वासन दिया कि दारू बन्दी जो रेटेट लागू करेंगी उनको हम आर्थिक सुविधा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि दारूबंदी एक ही मंत्रालय कर सकता है और वह मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा की वजह से ही हम लोग नशाबन्दी कर सकते हैं, न कि डंडे के बल पर और न ही गृह-मंत्रालय से और न ही उसके लिये अलग मिनिस्ट्री स्थापित करने से। जो पैसा नशा बन्दी लागू करने के लिये दिया जाता है वह पानी के माफिक खर्च किया जाता है और उसका कहीं भी उपयोग नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जी आप अर्थ मंत्री जी से कहें वह पैसा शिक्षा मंत्रालय को दो, उसको हम शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेंगे, शिक्षकों के बारे में खर्च करेंगे, शालाओं को इमारतों के लिये खर्च करेंगे, छात्रवृत्तियां देने के बारे में खर्च करेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि मोरारजी भाई जो दारू बंदी के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे वह शिक्षा मंत्रालय कर सकेगा और भारत में शान्ति प्रस्थापित हो सकेगी।

मोलहु प्रसाद : मान्यवर, क्या हमें मौका नहीं मिलेगा?

MR. CHAIRMAN : Extra time was given to Mr. Yadav. I am not going to give any time now.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति जी, अखबारों में देखा है कि बिहार के भी शिक्षक हड़ताल करने की नोटिस दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों ने हड़ताल की है। मैं अपने माननीय मंत्री जी से, तीनों ही मंत्री हमारे शिक्षा प्रेमी हैं, आग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें।

लेकिन एक बात मैं शिक्षकों के लिये भी कहूंगा कि शिक्षक लोग आजकल पूरी दिलचस्पी से पढ़ाने नहीं हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल के हों या हाई स्कूल के हों, क्यों कि उनकी रुचि पढ़ाने से हट गयी है। आज शिक्षकों की तादाद इतनी बढ़ गयी है कि स्कूलों के सब-इंस्पेक्टर पढ़ाने का काम नहीं देखते हैं बल्कि

[श्री विभूति मिश्र]

बिल बनाने में दक्षिणा लेते है। यह काम तो हम ब्राह्मणों का था। मैं देखता हूं कि प्रशासन की ढिलाई है और जो शिक्षा वर्ग के प्रशासक हैं वह भी काम नहीं करते। लेकिन साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि शिक्षकों की जो उचित मांगें हैं उसके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये और उनको सस्पेंड करना, उन के खिलाफ कार्यवाही करना यह सब नहीं होना चाहिये। क्योंकि वही शिक्षक वोटर भी है और नागरिक भी है, जैसे हम यहां मेम्बर भी हैं और वोटर भी हैं इसी प्रकार हम को शिक्षकों के लिये भी सोचना चाहिये, जैसी उनकी हालत है। इसलिये मैं कहूंगा कि बिहार में अभी तो उन्होंने नोटिस दिया है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिगड़ गयी है, इसलिये बिहार को सम्हालिये, दोनों प्रदेशों को सम्हालिये। चुनाव आ रहा है, विरोधी दल उसका फायदा उठाना चाहता है। उसको वह फायदा न उठाने दीजिये।

श्री राम सेवक यादव : उनको तनख्वाह दे दीजिये, हम बिल्कुल फायदा नहीं उठायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : इसलिये मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार कोई उचित कार्यवाही करे। सरकार फिजूलखर्ची में से पैसा निकाल कर इस को दे सकती है। शिक्षक ही नेशन के बिल्डर हैं क्योंकि इन की पढ़ाई की वजह से कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो सकता है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अधिष्ठाता महोदय, सदन के विभिन्न सदस्यों ने शिक्षकों की हड़ताल के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है, उससे सरकार भी सहयोग करती है। मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का जो वेतनमान है वह हिन्दुस्तान में सभी प्रान्तों के वेतनमान से कम है। यों पिछले वर्षों में मंत्री महोदय के कहने पर पंजाब, हरियाणा ने उनके वेतन में वृद्धि की है। साथ ही बिहार में जहां के बारे में अभी माननीय सदस्य ने कहा, वहां के शिक्षक संघ से मिल कर बिहार सरकार ने निर्णय किया, और वह उचित था, उन्होंने सिद्धान्त रूप में कोठारी कमीशन के वेतन मान को स्वीकार कर लिया और यह कहा कि इस को हम क्रमशः कार्यान्वित करेंगे।

माननीय सदस्य बनर्जी साहब ने जो कहा वह बात ठीक है। जब मैं पिछली बार लखनऊ में था तो मैंने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया था कि वह, जिस आधार पर बिहार सरकार ने किया है, उस आधार पर विचार करें। लेकिन यह अब तक उन के लिये सम्भव नहीं हो सका।

जो पांच उनकी मांगें हैं उन मांगों के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसका मैं खंडन नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं सरकार की तरफ से बार बार, विश्वास मानिये, इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षकों के प्रति, उनकी मांगों के प्रति, पूरी सहानुभूति है और हम पूरी तरह से आकृष्ट हैं। लेकिन कुछ जो बातें माननीय सदस्यों ने अभी कही हैं वे बातें सही नहीं हैं यद्यपि जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी जो मांगें है सिद्धान्ततः उनकी मांगों के औचित्य से हम पूर्ण रूप में सहमत है। यह जो सरकारी खजाने से देने की बात कही गयी इस संबंध में संविद सरकार ने कुछ आंकड़े तैयार किये थे जिनके अनुसार 18 करोड़ कुछ लाख रु० है, 9 करोड़ कुछ लाख रुपया ग्रान्ट्स के रूप में दिया जाता है और 9 करोड़ कुछ लाख रुपया फीस के रूप में लेते हैं। खर्च 16 करोड़ है। तो इस तरह से दो करोड़ की बचत है। इस सम्बन्ध में कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा हिसाब संविद सरकार ने नहीं किया है.....

उत्तर प्रदेश की सरकार से हमने पता लगाया था। हमारे शर्मा जी ने बताया कि उस समय के शिक्षा मन्त्री और उपमुख्य मंत्री ने फाइल पर दस्तखत भी किए थे। दुर्भाग्य है कि आज ऐसी कोई फाइल उत्तर प्रदेश

सरकार में नहीं मिल रही है जिस पर उनके दस्तखत हो या वे आंकड़े मिल सकें। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि उनको समय पर भुगतान किया जाए, यह सही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मैनेजमेन्ट हैं जोकि समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में वहां की सरकार ने निर्णय किया है कि जहां-जहां ऐसी बातें हों, ज्योंही उसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाए तो सरकार की ओर से जो ग्रान्ट दी जाती है उसमें से पैसा काटकर उन शिक्षकों की तनख्वाह दे दी जाए। इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। . . . (**व्यवधान**) . . .

18 hrs .

ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। चूंकि सिग्नेचर नहीं है इसलिए फाइल है ही नहीं। लेकिन मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं फाइल है या नहीं। मैं तो इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो उनकी मांगें हैं, जैसे कि मंहगाई भत्ते का प्रश्न है, यह सही है कि एक अगस्त, 1967 को जो मंहगाई-भत्ता वहां के सरकारी कर्मचारियों को दिया गया, वही संविद सरकार ने शिक्षकों को दिया, लेकिन एक अगस्त, 1968 को जो मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया वह शिक्षकों को नहीं मिला। इसका कारण यह बताया गया कि उस समय जो मंहगाई-भत्ता हमने स्वीकार किया, एक अगस्त, 1967 को, वह एडहाक रूप में था। लेकिन हम आप को विश्वास दिलाते हैं कि वास्तव में यह जो बात कही जाती है कि सर्कुलर हिन्दी या अंग्रेजी में इश्यू किया गया है उसे हम देखना चाहते हैं कि उसके क्या अर्थ हैं? वास्तव में यह-बात है कि वह एडहाक था या यह था कि सरकारी कर्मचारियों की पैरिटी तमाम शिक्षकों पर भी लागू हो। . . .

श्री स० मो० बनर्जी : इसमें पैरिटी की बात है।

श्री भगवत झा आजाद : जो आप बता रहे हैं, उसको मैंने भी पढ़ा है। मैं यह कह रहा हूं कि हम देखना चाहते हैं कि एक अगस्त, 1967 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मंहगाई भत्ते की पैरिटी घोषित की वह वास्तव में एडहाक रूप में थी, आगे आने वाली इंक्रीमेंट में नहीं थी या सभी के लिए लागू थी। लेकिन जो आप दिखा रहे हैं वह तो मैंने भी पढ़ा है।

श्री एस० एम० जोशी : पैरिटी शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी।

श्री भगवत झा आजाद : जोशी जी सही कह रहे हैं लेकिन न वे यह कहते हैं कि एक अगस्त, 1967 को जो हमने आर्डर निकाला वह उस समय की पैरिटी के लिए था। फिर भी मैं इस बात पर जोर नहीं देता। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कोठारी कमीशन ने जो वेतन मान निश्चित किए हैं वह एक मैट्रिक ट्रेन्ड के लिए कम से कम 150 रु० और अधिक से अधिक 250 रु० हैं और इसी प्रकार से ट्रेन्ड ग्रैजुएट्स और पोस्ट-ग्रैजुएट्स के लिए हैं, हम चाहते हैं कि वे वेतनमान सभी प्रान्तों में लागू किए जायें और इसके लिये हम सभी सरकारों से कह रहे हैं जिसके फलस्वरूप पंजाब ने और हरियाणा ने किया, बिहार की सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया और इस साल में महाराष्ट्र की सरकार ने भी किया. . . .

श्री विभूति मिश्र : बिहार में भी रेगुलर पैमेन्ट नहीं होता है।

श्री भगवत झा आजाद : मैंने बताया कि बिहार की सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। इस वर्ष में उनका खर्चा 3,85 लाख है। लेकिन मैं तो इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इन तमाम मांगों को जैसे कि महंगाई भत्ते की है, जिसके लिए ट्रेजरी से देने की बात है और आपने जो तमाम आंकड़े दिए, उसके सम्बन्ध में हमने

[श्री भागवत झा आजाद]

उत्तर प्रदेश की सरकार से बात चीत की। जहां आप यह कहते हैं कि इससे दो करोड़ का नफा होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सैम्पिल सर्वे सौ स्कूलों का पिछले अप्रैल में किया है और उसके आधार पर एक करोड़ रुपये की वृद्धि होगी क्योंकि इसके अनुसार वे चाहते हैं कि जो कामर्स और साइन्स के स्कूल हैं उनके विद्यार्थियों की फीस का 70 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा हो और जो आर्ट्स के हैं उनका 80 प्रतिशत जमा हो और फिर सरकार दे। तो वे कहते हैं कि इसके अनुसार ग्रान्ट्स-इन-एड में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और एक करोड़ रुपया देना होगा। फिर भी मैं इस बात पर जोर नहीं देता हूं। प्रमुख बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कम-से-कम 150 रुपये वहां के दो लाख शिक्षकों को दिये जायं तो उसके लिए काफी रुपया चाहिए। अभी इन तमाम मांगों की पूर्ति के लिए 676 लाख रुपया चाहिए। आप इस बात को मानेंगे कि इतनी बड़ी धनराशि के लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होगी और उन अतिरिक्त साधनों का प्रबन्ध टैक्स से, करों से, न कि नासिक प्रिंटिंग से, कर सकते हैं। फिर आपने बार-बार इस बात का हवाला दिया है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन है और राष्ट्रपति शासन किसी प्रान्तीय सरकार को इतना बड़ा खर्चा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, वह खर्चा जो कि न सिर्फ कुछ वर्षों के लिए बल्कि आगे आने वाले तमाम वर्षों के लिए हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न अब एक दो महीने का ही है। जब तक वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं आती, इतना बड़ा खर्चा हम नहीं कर सकते है फिर भी हम यह जरूर चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को सलाह भी दे रहे हैं.....

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो साल पहले टीचर्स की तनख्वाह के लिए सात करोड़ रु० की वृद्धि की थी और वह दे रही है। अब उसके बाद दो साल बीत गये है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि इतनी ज्यादा रकम अगर है तो कम-से-कम उसका 50 फीसदी ही केंद्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की दिक्कत को देखते हुए दे दीजिए।

श्री भगवत झा आजाद : यह बात भी मैं स्पष्ट कर दूं। इस बात का हवाला दिया गया है कि सरकार 80 प्रतिशत दे। केंद्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए, जहां तक समन्वय का प्रश्न है, हायर एजूकेशन के कोआर्डिनेशन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए दिया है। लेकिन जहां तक प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण देश के सारे प्रान्तों को देना केंद्रीय सरकार के लिए सम्भव नहीं है। प्रान्तीय सरकारों को ही इसके लिए साधन एकत्रित करने होंगे और उसी के अंतर्गत यह करना होगा। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिश्रुति अभी नहीं दे सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह बात जल्द ही की जाए। परन्तु जबतक चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं आती, इतनी अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को मैंने आज भी सलाह दी है और प्रधान मंत्री ने स्वयं वहां के राज्यपाल से बात चीत की थी। 12 दिसम्बर को शिक्षकों के प्रतिनिधियों से जो बातें हुई वह तो हुई, बनर्जी साहब ने ठीक ही कहा है कि सरकार यह बात मानकर न बैठ जाए कि शिक्षक यह कहते हैं कि जबतक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तबतक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं और हम यह नहीं समझते कि हमारे शिक्षक यह कहेंगे कि जब तक सारी पांचों मांगें पूर्ण रूप में नहीं मान ली जायेंगी, तब तक हम बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के

शिक्षक अपनी हड़ताल समाप्त करें। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कह रहे हैं, कह चुके हैं और फिर भी कहेंगे कि वे आपस में बात-चीत करें और जहां तक सम्भव हो, उन मांगों में से कुछ मांगें जो कि सरकार की क्षमता के अन्दर हों, स्वीकार करें। हम शिक्षकों से भी अपील करेंगे कि वे अपनी हड़ताल को उठा लें। आज शिक्षक जेल में हैं, इस बात से हमें कोई प्रसन्नता नहीं है। हम इस में बड़ा दुख का अनुभव करते हैं कि राष्ट्र-निर्माताओं को यह करना पड़ा। लेकिन प्रश्न यह है कि जबतक हड़ताल जारी है तो उसका नतीजा क्या होगा, उन्हें हम एक तरफ छोड़ेंगे लेकिन दूसरी तरफ उनकी हड़ताल जारी रहेगी, वे फिर जेलों में जायेंगे। इसलिए जबतक इस प्रश्न का समाधान न हो जाए, जबतक एक टेबिल पर बैठकर इसका निर्णय न कर लिया जाए, तबतक यह सम्भव नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि दोनों तरफ से एक ऐसा एटमास्फियर क्रिएट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार और शिक्षक संघ दोनों ही उस एटमास्फियर क्रिएट करने का प्रयत्न करें।

18. 10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 16, 1968/Agrahayana 25, 1890 (Saka).

NDPI-1010-3-69.